



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 233]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 6, 2009/आषाढ़ 15, 1931

No. 233]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 6, 2009/ASADHA 15, 1931

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बजट प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 2009

सं. एफ. 2(36)-बी(डी)/2009.-निम्नलिखित को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :-

“बजट 2009-2010

वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी का भाषण

6 जुलाई, 2009

अध्यक्ष महोदय,

मैं वर्ष 2009-10 का बजट प्रस्तुत करने जा रहा हूँ।

2. आज से मात्र 140 दिन पूर्व, मुझे 2009-10 का अंतरिम बजट प्रस्तुत करने का सौभाग्य मिला था। यह मेरे लिए अत्यन्त गौरव की बात है कि मुझे नई सरकार के कार्यभार संभालने के बाद नियमित बजट प्रस्तुत करने का दायित्व दिया गया है।

3. कांग्रेस के नेतृत्व में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार नए जनादेश के साथ फिर सत्ता में आयी है। जैसाकि माननीय प्रधानमंत्री, डा. मनमोहन सिंह ने हाल ही में कहा था, “यह जनादेश

निरन्तरता, स्थिरता और समृद्धि के लिए है। यह जनादेश समावेशी विकास और समतापरक विकास के लिए है।” हम इस जनादेश को विनम्रतापूर्वक और इस दृढ़ संकल्प के साथ स्वीकार करते हैं कि हम इस राष्ट्र की भलाई के लिए अपनी पूर्ण क्षमार्थ्य से प्रयत्नशील रहेंगे।

4. मैं जनता द्वारा हमारी सरकार में प्रकट किए गए विश्वास और तत्संबंधी जिम्मेदारियों के प्रति पूरी तरह सचेत हूँ। मैं युवा भारत की बढ़ती हुई उम्मीदों की वृहत् चुनौती को भली भाँति समझता हूँ। यह युवा पीढ़ी व्यग्र परन्तु कर्मठ है और वह प्रदत्त अवसरों को हथियाने के लिए तत्पर है। हमारी फिर से यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि हम उन अवसरों को पैदा करें, उनकी सुसाध्यता व निरन्तरता बनाए रखें।

5. वर्ष 2009-10 के अंतरिम बजट में, मैंने कहा था कि नई सरकार को 2009-10 के लिए, मध्यावधि परिप्रेक्ष्य में अपनी नीतियों को दृढ़तर बनाने की आवश्यकता होगी जिनमें निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना होगा :

- (क) विस्तारित समयावधि के दौरान कम से कम 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की विकास दर बनाए रखना;
- (ख) प्रति वर्ष लगभग 12 मिलियन नए कार्य अवसरों के सृजन हेतु समावेशी विकास संबंधी प्रणालियों को सुदृढ़ करना;
- (ग) गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों के अनुपात को वर्तमान स्तरों से घटाकर वर्ष 2014 तक आधे से कम करना;

- (घ) यह सुनिश्चित करना कि भारतीय कृषि में 4 प्रतिशत की वार्षिक दर से वृद्धि बनी रहे;
- (ङ) वर्ष 2014 तक, अवसंरचना में सकल घरेलू उत्पाद का 9 प्रतिशत से अधिक निवेश बढ़ाना;
- (च) वैश्विक प्रतिस्पर्धा की चुनौती का सामना करने और निर्यात में विकास गति बनाए रखने हेतु भारतीय उद्योग की सहायता करना;
- (छ) देश में आर्थिक विनियामक ढांचे को सुदृढ़ करना और उसमें सुधार लाना;
- (ज) दुर्बल वर्गों को सीधे सहायता प्रदान करके सामाजिक सुरक्षा तंत्रों के अधिकार क्षेत्र और पहुंच को बढ़ाना;
- (झ) प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान करने के तंत्र को सुदृढ़ बनाना ताकि देश में निवारक और उपचारात्मक स्वास्थ्य परिचर्या में सुधार लाया जा सके;
- (ञ) वैश्विक मानकों की एक ऐसी प्रतिस्पर्धात्मक, प्रगतिशील और पूर्ण विनियमित शिक्षा प्रणाली विकसित करना जो समाज के सभी वर्गों की आकांक्षा को पूरी करे;
- और
- (ट) एकीकृत ऊर्जा नीति का पालन करते हुए ऊर्जा सुरक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में बढ़ना।

6. सरकार इस कार्य में अन्तर्निहित चुनौतियों से वाकिफ है, विशेषकर ऐसे समय जब विश्व अभूतपूर्व वित्तीय संकट और आर्थिक मंदी से जूझ रहा है। इसने भारत को भी प्रभावित किया है। हम जहां अपनी कथनी को करनी में बदलने के लिए कृतसंकल्प हैं, वहीं सदस्य इस बात को मानेंगे कि अकेले बजट भाषण से हमारी सभी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है, ना ही केन्द्रीय बजट ऐसा करने का एकमात्र साधन है। फिर भी यह सरकार की दूरदृष्टि को प्रकट करने का एक महत्वपूर्ण साधन है, विशेषकर तब, जब हम एक नया कार्यकाल आरंभ कर रहे हैं। अगले एकाध बटे में मेरा ऐसा ही करने का प्रस्ताव है, जब मैं इन चुनौतियों पर ध्यान केन्द्रित करूंगा और अल्पावधिक और मध्यावधिक परिप्रेक्ष्यों में सरकार के दृष्टिकोण को रेखांकित करूंगा।

7. पहली चुनौती है अर्थव्यवस्था में शीघ्रतिशीघ्र 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की उच्च सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर फिर से प्राप्त करना। आय में वृद्धि अपने में महत्वपूर्ण है परन्तु यह उन संसाधनों के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जिन्हें यह सृजित करती है। ये संसाधन उन निर्णायक अन्तरालों को पाटने हेतु साधन उपलब्ध कराते हैं, जो हमारे विकासात्मक प्रयासों, विशेषकर हमारी जनसंख्या के दुर्बल वर्गों के कल्याण के संबंध में रह जाते हैं।

8. दूसरी चुनौती समावेशी विकास के एजेन्डे को सुदृढ़ और व्यापक बनाने की है और यह सुनिश्चित करना है कि कोई व्यक्ति, समुदाय या क्षेत्र विकास की प्रक्रिया में प्रतिभागी होने और उससे लाभान्वित होने के अवसर से वंचित न रह जाए।

9. तीसरी चुनौती है सरकार में नई ऊर्जा का संचार करना और कितरण प्रणालियों में सुधार लाना। हमारी संस्थाओं को सभी नागरिकों को पारदर्शिता और जवाबदेही युक्त उच्च गुणवत्ता वाली लोक सेवाएं, सुरक्षा और कानून सम्मत शासन मुहैया कराना चाहिए।

अर्थव्यवस्था का सिंहावलोकन

10. अध्यक्ष महोदया, अन्तरिम बजट प्रस्तुत करते समय, मैंने आर्थिक स्थिति का विस्तृत विश्लेषण दिया था। अपनी बात को दुहराए बिना, मैं इस तथ्य पर जोर देना चाहूंगा कि पिछले पांच वर्षों में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार द्वारा प्रशस्त विकास का पथ, अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर में तेजी और राजस्व उगाही में तेजी के कारण संभव हुआ है। इस अवधि में संवृद्धि का मुख्य कारक निजी निवेश रहा है, जो प्रमुखतया घरेलू संसाधनों द्वारा निधिपोषित रहा है। सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर में पिछले तीन वित्त वर्षों में 9 प्रतिशत से अधिक की औसत वृद्धि हुई थी, जो वर्ष 2008-09 के दौरान कम होकर 6.7 प्रतिशत रह गयी है। इसने अर्थव्यवस्था के कतिपय क्षेत्रों में रोजगार सृजन की गति और व्यापारिक समुदाय की निवेश भावनाओं को प्रभावित किया है। इसके परिणामस्वरूप, सरकार की राजस्व वृद्धि में भी काफी कमी आई है। वर्ष 2008-09 की एक अन्य विशेषता अगस्त 2008 में थोक मूल्य सूचकांक में लगभग 13 प्रतिशत तक की तीव्र वृद्धि और मार्च 2009 में समान रूप से लगभग 0 प्रतिशत की तीव्र गिरावट है। इन घटनाक्रमों का विस्तृत विश्लेषण जहां गत बृहस्पतिवार को संसद के दोनों सदनों में पेश आर्थिक समीक्षा 2008-09 में प्रस्तुत किया गया है, मैं कुछ पहलुओं पर आपका ध्यान आकर्षित करता हूं।

11. भारत की अर्थव्यवस्था का ढांचा पिछले दस वर्षों में तेजी से बदला है। विदेशी व्यापार और वैदेशिक पूंजी प्रवाह अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण भाग हैं और इसी प्रकार सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का 50 प्रतिशत से अधिक का अंशदान है। सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में पण्य व्यापार (निर्यात तथा आयात) का हिस्सा पिछले दशक के दौरान दुगुने से अधिक होकर 2008-09 में 38.9 प्रतिशत हो गया है। इसी प्रकार, वस्तुओं और सेवाओं का संयुक्त व्यापार भी इस अवधि के दौरान दुगुना होकर 47 प्रतिशत हो गया है। सकल पूंजी प्रवाह वैश्विक वित्तीय संकट के चलते गिरने से पूर्व, 2007-08 में सकल घरेलू उत्पाद के 9 प्रतिशत से अधिक के शीर्ष स्तर पर पहुंच गया था। विदेशी पूंजी के अंतर्वाह में महत्वपूर्ण वृद्धि, घरेलू बचत-निवेश अंतर को पाटने में इतनी अधिक नहीं है, अपितु अर्थव्यवस्था की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्तीय संसाधनों की मध्यस्थता को सुसाध्य बनाने हेतु महत्वपूर्ण है।

12. शेष विश्व के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था के बढ़ते हुए एकीकरण ने नए अवसरों के साथ-साथ नई चुनौतियां भी उत्पन्न की हैं। इसने उच्च संवृद्धि को बनाए रखने के कार्य को अधिक जटिल बना दिया है। पिछले एक माह के दौरान, हमने अल्पावधिक आर्थिक पुनःरुत्थान तथा मध्यावधि आर्थिक वृद्धि दोनों में सरकार के प्रयासों का समालोचनात्मक मूल्यांकन किया है। आर्थिक पुनःरुत्थान और वृद्धि केन्द्र और राज्य सरकारों का एक सामूहिक प्रयास है। अतः इस

बजट की तैयारियों के भाग के रूप में, मैंने पहली बार राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ बैठक की। मैं हर वर्ष ऐसा करना चाहता हूँ।

आर्थिक पुनरुत्थान की राह पर

अल्पावधिक उपाय

13. भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्विक मंदी के नकारात्मक प्रभाव का सामना करने के लिए, सरकार ने मांग बढ़ाने तथा रोजगार और लोक आस्तियां सृजित करने हेतु सरकारी परियोजनाओं पर बढ़े हुए व्यय के लिए कर राहत के रूप में तीन संकेन्द्रित राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेज प्रदान कर इस दिशा में पहल की। भारतीय रिजर्व बैंक ने उत्पादक सेक्टरों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्तीय प्रणाली से निधियों के प्रवाह को सुसाध्य बनाने हेतु अनेक मौद्रिक सहजीकरण और नकदी बढ़ाने के उपाय किए।

14. इस राजकोषीय समायोजन से राजकोषीय घाटा, 2007-08 में सकल घरेलू उत्पाद के 2.7 प्रतिशत से बढ़कर 2008-09 में 6.2 प्रतिशत हो गया। 2007-08 और 2008-09 के वास्तविक आंकड़ों के बीच आए अंतरों का कारण कुल राजकोषीय प्रोत्साहन रहे हैं। 2008-09 के लिए मौजूदा बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद के 3.5% पर राजकोषीय प्रोत्साहनों की राशि 1,86,000 करोड़ रुपये बैठती है।

15. ये उपाय 2008-09 में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर में गिरावट रोकने में प्रभावशाली रहे और हमने 6.7 प्रतिशत की वृद्धि दर प्राप्त की। घरेलू उद्योग में पुनरुद्धार के संकेत हैं और लगता है कि विदेशी निवेशक भी पिछले दो महीनों से भारतीय बाजार में लौट रहे हैं। यह संभव है कि सितंबर 2008 में वैश्विक वित्तीय मंदी से प्रभावित दो बहुत खराब तिमाहियां निकल चुकी हैं। यद्यपि वैश्विक वित्तीय दशाओं ने हाल के कुछ महीनों में सुधार दर्शाए हैं, परन्तु वैश्विक अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार से जुड़ी अनिश्चितताएं अभी बाकी हैं। इसलिए हम सावधानी बरतना नहीं छोड़ सकते हैं। हम अर्थव्यवस्था को और प्रोत्साहन देने के अपने प्रयास जारी रखेंगे।

16. अध्यक्ष महोदया, मैं जो अब प्रस्तुत कर रहा हूँ, ये 'आरंभिक उपाय' हैं। मेरा प्रयास होगा कि बजट बनाने की प्रक्रिया को अधिक सहभागितापूर्ण और निरंतर प्रक्रिया वाला बनाया जाए।

अवसंरचना विकास

17. हमने अवसंरचना में सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए अवसंरचना परियोजनाओं को दीर्घावधिक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु विशेष प्रयोजन माध्यम के रूप में भारत अवसंरचना वित्त कम्पनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) का गठन किया था। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि इस कम्पनी को अपना अधिदेश उचित ढंग से पूरा करने के लिए अधिक नम्यता प्रदान की जाए।

18. 'वित्तपोषण प्राप्त करना' अवसंरचना परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु दीर्घावधिक निधियां जारी करने की एक स्वीकार्य अंतरराष्ट्रीय प्रक्रिया है। इसका प्रयोग अवसंरचना परियोजनाओं के वित्तपोषण से उत्पन्न वाणिज्यिक बैंकों की आस्ति देयता बेमेलता का

प्रभावशाली ढंग से समाधान करने में किया जा सकेगा और इससे नई परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए पूंजी भी सहज उपलब्ध होगी। आईआईएफसीएल बैंकों के साथ परामर्श करके 'वित्तपोषण प्राप्त करने' की योजना बनाएगा जो अवसंरचना क्षेत्र को वृद्धिकारी उधार देना सुसाध्य बनाएगी।

19. सरकार को दूरसंचार विद्युत उत्पादन, हवाई-अड्डों, बन्दरगाहों, सड़कों जैसे अनेक अवसंरचना सेक्टरों में और यहां तक कि सरकारी-निजी भागीदारी के माध्यम से रेलवे में भी निजी निवेश आकर्षित करने में कुछ सफलता मिली है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि अवसंरचना परियोजनाओं को मौजूदा मंदी से उत्पन्न वित्तपोषण संबंधी कठिनाइयों का सामना न करना पड़े, जैसा मैंने अपने अंतरिम बजट भाषण में इंगित किया था, सरकार ने निर्णय लिया है कि आईआईएफसीएल अगले पंद्रह से अठारह महीने के दौरान महत्वपूर्ण सेक्टरों में सरकारी-निजी भागीदारी परियोजनाओं के लिए वाणिज्यिक बैंकों के ऋणों के 60 प्रतिशत का पुनर्वित्तपोषण करेगा। आईआईएफसीएल और बैंक अब अवसंरचना में 100 हजार करोड़ रुपये के कुल निवेश वाली परियोजनाओं की सहायता करने की स्थिति में हैं। इन उपायों के साथ हम अवसंरचना में सरकारी निवेश बढ़ाना आरंभ कर रहे हैं। इससे ऐसे निवेश को काफी बढ़ावा मिलेगा।

20. अर्थव्यवस्था के विकास के लिए अवसंरचना में निवेश महत्वपूर्ण है। मैंने केन्द्र और राज्य सरकारों में अपने सहयोगियों से आग्रह किया है कि आधारभूत संरचना की परियोजनाओं के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए नीतिगत, विनियामक और संस्थागत अड़चनें दूर करें। मैं अपनी ओर से यह सुनिश्चित करना चाहूंगा कि इस क्षेत्र के लिए पर्याप्त निधियां उपलब्ध कराई जाती हैं।

राजमार्ग और रेलवे

21. मौजूदा वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को आवंटन, 2008-09 (बजट अनुमान) की तुलना में 23 प्रतिशत बढ़ाया जा रहा है। मैंने रेलवे के लिए 2009-10 के अंतरिम बजट में किए गए 10,800 करोड़ रुपये के आवंटन को भी बढ़ाकर 15,800 करोड़ रुपये कर दिया है।

शहरी अवसंरचना

22. जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) शहरी अवसंरचना में महत्व पर राज्य सरकारों का ध्यान पुनःकेंद्रित करने का एक महत्वपूर्ण साधन रहा है। इस मिशन की भूमिका को मान्यता देते हुए, मौजूदा बजट में इस योजना के लिए आवंटन 87 प्रतिशत बढ़ाकर 12,887 करोड़ रुपये किया जा रहा है। शहरी गरीबों की हालत सुधारने के लिए शहरी गरीबों को आवास और मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था करने हेतु, मैं मौजूदा वर्ष के बजट आवंटन को बढ़ाकर 3973 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव करता हूँ। इसमें राजीव आवास योजना नामक नई योजना के लिए प्रावधान है। इस योजना की घोषणा भारत की महामहिम राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में की थी। इस स्कीम के मापदंड तैयार किए जा रहे हैं। इसका आशय पांच वर्ष की अवधि में देश को मलिन बस्ती मुक्त बनाना है।

बृहन् मुंबई तूफानी जल निकासी परियोजना

23. मुंबई में बाढ़ की समस्या का समाधान करने के लिए, 2007 में बृहन् मुंबई तूफानी जल निकासी परियोजना आरम्भ की गई थी। इस परियोजना की 1200 करोड़ रुपये की सम्पूर्ण अनुमानित लागत केंद्रीय सहायता के माध्यम से वित्तपोषित की जा रही है। 2008-09 तक, इस परियोजना के लिए 500 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है। मैंने, यह परियोजना शीघ्र पूरी करने के लिए, इस परियोजना हेतु अन्तरिम बजट अनुमान में किए गए 200 करोड़ रुपये के प्रावधान को बढ़ाकर 500 करोड़ रुपये कर दिया है।

विद्युत

24. त्वरित विद्युत विकास और कार्यक्रम बिजली की मांग और आपूर्ति के बीच अंतर कम करने की एक महत्वपूर्ण योजना है। मैं इस योजना के लिए आवंटन बढ़ाकर 2080 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव करता हूँ। यह 2008-09 के बजट अनुमान में किए गए आवंटन से 160 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि है।

गैस

25. हाल में देश के पूर्वी तट पर कृष्णा-गोदावरी थाले में मिली प्राकृतिक गैस से ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में उभर रही इस गैस का घेरलू उत्पादन दोगुना होना निश्चित है। देश में द्रवित प्राकृतिक गैस (एलएनजी) अवसंरचना का भी विस्तार किया जा रहा है। सरकार लंबी दूरी के गैस हाइवे के लिए एक खाका तैयार करने का प्रस्ताव करती है जिससे प्राकृतिक गैस ग्रिड का मार्ग प्रशस्त होगा। इससे देश के कोने-कोने में गैस ले जाना आसान होगा।

असम गैस क्रैकर परियोजना

26. अप्रैल 2006 में स्वीकृत असम गैस क्रैकर परियोजना 5461 करोड़ रुपये की लागत से क्रियान्वित की जा रही है। इस परियोजना के लिए 2138 करोड़ रुपये की पूंजी सब्सिडी केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी। इस परियोजना के लिए परिव्यय को उपयुक्त ढंग से बढ़ाया जा रहा है।

कृषि विकास

मैं अब कृषि विकास की ओर आता हूँ।

27. कृषि हमारी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार रहा है। हमारी 60 प्रतिशत जनसंख्या इससे अपना आहार प्राप्त करती है। अभी हाल में, इस क्षेत्र में आयोजना आवंटन और पूंजी निर्माण में पर्याप्त वृद्धि से, इस क्षेत्र ने लगभग 4 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर्ज की है। 2008-09 में कृषि ऋण प्रवाह 2,87,000 करोड़ रुपये था। 2009-10 के लिए कृषि ऋण प्रवाह का लक्ष्य 3,25,000 करोड़ रुपये निर्धारित किया जा रहा है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, मैं 7 प्रतिशत प्रति वर्ष की ब्याज-दर पर प्रति किसान 3 लाख रुपये तक के ऋणों के लिए किसानों को अल्पावधिक फसल ऋणों हेतु ब्याज सहायता योजना जारी रखने का प्रस्ताव करता हूँ। मुझे यह घोषणा करते हुए भी प्रसन्नता हो रही है कि इस वर्ष के लिए सरकार उन किसानों को प्रोत्साहन के रूप में 1 प्रतिशत अतिरिक्त सहायता देगी

जो अपने अल्पावधिक फसल ऋणों की अदायगी निर्धारित समय पर कर देते हैं। इस प्रकार, इन किसानों के लिए ब्याज दर कम होकर 6 प्रतिशत वार्षिक हो जाएगी। मैं, इसके लिए, अन्तरिम ब.अ. की तुलना में 411 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट प्रावधान कर रहा हूँ।

किसानों के लिए ऋण राहत

28. अनुमानतः 40 मिलियन किसानों को समाविष्ट करते हुए लगभग 71,000 करोड़ रुपये की एक बारगी बैंक ऋण माफी पिछले बजट की मुख्य विशेषताओं की एक विशेषता थी। कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना (2008) के अंतर्गत, दो हेक्टेयर से अधिक भूमि वाले किसानों को अपने अतिदेयों के 75% की अदायगी करने के लिए 30 जून, 2009 तक का समय दिया गया था। मानसून के विलंब से आने के कारण, मैं इस अवधि को 31 दिसंबर, 2009 तक छः महीने बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूँ।

29. यह पता लगा है कि महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में बड़ी संख्या में किसानों ने निजी ऋणदाताओं से ऋण ले रखे हैं और ऋण माफी योजना में उन्हें शामिल नहीं किया गया है। इस मुद्दे पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इस मुद्दे की व्यापक पड़ताल करने और भावी कार्ययोजना का सुझाव देने के लिए, मैं एक कार्यदल के गठन का प्रस्ताव करता हूँ।

त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम

30. त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के लिए, मैं अन्तरिम ब.अ. की तुलना में 1000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूँ। यह वर्ष 2008-09 (ब.अ.) के आवंटन की तुलना में 75 प्रतिशत अधिक है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) संबंधी आवंटन में भी वर्ष 2008-09 के बजट अनुमान की तुलना में 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जा रही है।

निर्यात वृद्धि की पुनः प्राप्ति

31. हमारे निर्यातकों ने, वैदेशिक क्षेत्र में अपने संबंधों के बल पर, वैश्विक आर्थिक संकट के आवेश को बरदाश्त कर लिया है। अतः यह उचित होगा कि हम अपने निर्यातकों को अल्पावधिक प्रतिकूल परिस्थितियों से बाहर निकलने में सहायता प्रदान करने के लिए हर संभव सहायता प्रदान करना जारी रखें। यह विशिष्ट रूप से इस प्रकार होगी :

- (क) बुरी तरह से प्रभावित क्षेत्रों को 95 प्रतिशत वर्धित निर्यात ऋण और गारंटी निगम (ईसीजीसी) कवर प्रदान करने हेतु दिसम्बर, 2008 में समायोजन सहायता योजना शुरू की गयी थी जिससे कि निर्यातकों को होने वाली कठिनाइयों को कम किया जा सके। निर्यात में जारी संकुचन के मद्देनजर, मैं इस योजना के फायदों को मार्च, 2010 तक बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूँ।
- (ख) बाजार विकास सहायता योजना विकासशील नए बाजारों में निर्यातकों को सहायता प्रदान करती है। कई पारम्परिक बाजारों के अभी भी वित्तीय दबाव में होने के मद्देनजर,

नए बाजारों को पहचानने और विकसित करने के लिए अधिक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। मैं इस योजना के लिए ब.अ. 2008-09 की तुलना में 148 प्रतिशत की वृद्धिकर के 124 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूँ।

- (ब) वैश्विक मंदी से रोजगारोन्मुखी निर्यात क्षेत्र को मदद करने के उद्देश्य से, सरकार ने सात ऐसे क्षेत्रों के लिए लदान-पूर्व ऋण पर 2 प्रतिशत की ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता प्रदान की थी। इन क्षेत्रों में हथकरघा सहित कपड़ा, हस्तशिल्प, कालीन, चमड़ा, रत्न और आभूषण, समुद्री उत्पाद और लघु एवं मध्यम निर्यातक शामिल हैं। मैं ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता की 30 सितम्बर, 2009 की मौजूदा समय सीमा को 31 मार्च, 2010 तक बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूँ।

- (घ) अतिलघु, लघु और मध्यम उद्यमों (एम.एस.एम.ई.) पर निर्यात में हुई मंदी का प्रभाव पड़ा है और घरेलू मांग पर वैश्विक संकट का अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा है। इस क्षेत्र को सहायता प्रदान के लिए, मैं ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) से लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) को एक विशेष निधि प्रदान कर उचित ब्याज दरों पर ऋण प्रवाह को आसान बनाने का प्रस्ताव करता हूँ। अतिलघु और लघु उद्यमों (एमएसई) को ऋण प्रदान करने के लिए, 4,000 करोड़ रुपए की यह निधि बैंकों और राज्य वित्त निगमों (एसएफसी) को प्रोत्साहित करेगी और मौजूदा वित्तीय वर्ष के दौरान एमएसई को 50 प्रतिशत वृद्धिकारी उधार प्रदान करने को पुनः वित्तपोषित किया जाएगा।

- (ङ) फरवरी 2009 में, प्रिंट मीडिया को प्रोत्साहन पैकेज दिया गया जिसके तहत डीएवीपी विज्ञापनों पर 15 प्रतिशत एजेन्सी कमीशन की माफी और गैर-सरकारी विज्ञापनों में राजस्व हानि के दस्तावेजी प्रमाण देने पर विशेष राहत के रूप में अदा की जाने वाली डीएवीपी दरों में 10 प्रतिशत वृद्धि की गई। चूंकि प्रिंट मीडिया अभी भी कठिन दौर से गुजर रहा है, अतः मैंने प्रोत्साहन पैकेज को 30 जून, 2009 से 31 दिसम्बर, 2009 तक और छः माह के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया है।

मध्यावधिक निरंतरता

32. दीर्घावधिक विवेक और राजकोषीय निरंतरता के उद्देश्यों हेतु, अल्पावधिक राजकोषीय प्रोत्साहनों को संतुलित किया जाएगा। मैं कौटिल्य की इस उक्ति को उद्धृत करना चाहूंगा, “देश की समृद्धि के हित में, राजा को आपदाओं की संभावना का अनुमान लगाने में अध्यावसायी होना होगा, उनके घटित होने से पहले उन्हें टालने का प्रयास करना होगा, जो घटित हो गई हैं, उनसे निपटना होगा, आर्थिक क्रियाकलाप को सभी अवरोधों को दूर करना होगा और राज्य में होने

वाली राजस्व हानि को रोकना होगा”। मैं कौटिल्य की सलाह मानकर भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्विक संकट के नकारात्मक प्रभाव के समाप्त होते ही शीघ्रतिशीघ्र राजकोषीय घाटे के एफआरबीएम लक्ष्य पुनः प्राप्त करने का इरादा करता हूँ। मध्यावधिक राजकोषीय परिदृश्य के बारे में मुझे तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों की प्रतीक्षा है।

33. राजकोषीय घाटे को काबू में रखने के लिए, हमें मौजूदा वर्ष में ही संस्थागत सुधार संबंधी उपाय करने होंगे। स्थिर भुगतान संतुलन, संतुलित ब्याज दर और कॉरपोरेट निवेश के लिए विदेशी पूंजी का निरंतर प्रवाह बनाए रखने के लिए यह अनिवार्य है। इन उपायों में बजट के सभी पहलू जैसे सब्सिडी, कर, व्यय और विनिवेश सम्मिलित होंगे।

उर्वरक सब्सिडी

34. राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में, देश में वर्धित उर्वरक उपयोग से कृषि उत्पादकता में गिरावट चिंता का विषय है। उर्वरकों का संतुलित प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए, सरकार का इरादा मौजूदा उत्पाद मूल्य निर्धारण व्यवस्था के बजाए पोषण आधारित सब्सिडी व्यवस्था लाने का है। इससे बाजार में उचित कीमतों पर नवीन उर्वरक उत्पादों की उपलब्धता होगी। उर्वरक विनिर्माण क्षेत्र को नियंत्रण-मुक्त करने से, इस क्षेत्र में नए निवेशों की संभावना बढ़ेगी। उचित समय पर, किसानों को सब्सिडी के सीधे अंतरण की प्रणाली अपनाने का भी इरादा है।

पेट्रोलियम और डीजल की मूल्य निर्धारण नीति

35. अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्यों को यह पता है कि तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के वैश्विक मूल्य वर्ष 2008-09 में अप्रत्याशित स्तरों तक बढ़ गए थे। हमारे पड़ोसी देशों सहित अधिकांश तेल आयातक देशों ने इन वैश्विक परिवर्तनों को प्रतिबिंबित करने के लिए अपने घरेलू मूल्यों को समायोजित कर लिया। यद्यपि तब से मूल्यों में गिरावट आ गई है, फिर भी ये मूल्य वैश्विक वित्तीय संकट के पश्चात् के निम्न स्तरों के लगभग दुगुने हैं। यह जानना महत्वपूर्ण है कि हमारी तीन चौथाई तेल खपत की पूर्ति आयात से की जाती है, अतः पेट्रोल और डीजल के घरेलू मूल्य मोटे तौर पर इन वस्तुओं के वैश्विक मूल्यों के अनुरूप करने होंगे। सरकार पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य निर्धारण की व्यवहार्य और टिकाऊ प्रणाली के संबंध में सलाह देने के लिए एक विशेषज्ञ दल का गठन करेगी। इसका ब्यौरा मेरे साथी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री द्वारा घोषित किया जाएगा।

कराधान

36. अब समय आ गया है कि हम उस प्रक्रिया को पूरा करें जिसे 1991 में विश्वास आधारित, सरल, निष्पक्ष कर प्रणाली के निर्माण के लिए शुरू किया गया था जिसमें प्रायः कोई छूट नहीं थी और दरें कम थीं और जिसकी रूपरेखा स्वैच्छिक अनुपालन के लिए तैयार की गई थी। आयकर विवरणी प्रपत्र सरल और प्रयोक्ता अनुकूल होना चाहिए। मैंने विभाग से सरल-II प्रपत्रों को शीघ्र प्रारंभ करने संबंधी कार्य करने के लिए कहा है। हमें एक ऐसी कर प्रणाली

की आवश्यकता है जो बलपूर्वक कर संग्रहण प्रविधि का उपयोग किए बिना ही, प्रत्येक वर्ष के अंत में लक्ष्यों को हासिल करने के लिए स्थायी आधार पर राजस्व का सृजन करे। मेरी अभिलाषा मौजूदा वर्ष में इस दिशा में संतुलित शुरुआत करना तथा यह सुनिश्चित करना है कि यह प्रक्रिया आगामी चार वर्षों में पूरी कर ली जाए। इस प्रक्रिया के अंत में, मैं आशा करता हूँ कि वित्त मंत्री विश्वास के साथ यह कह सकते हैं कि हमारे कर संग्रहक मधुमक्खियों की तरह हैं जो फूलों की शांति भंग किए बगैर, उनसे मधुरस का संग्रहण करते हैं परन्तु उनके पराग को फैलाते हैं जिससे कि सभी फूल खिलें और फल उत्पन्न करें।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों पर जनता का स्वामित्व

37. सरकारी क्षेत्र के उपक्रम राष्ट्र की सम्पत्ति हैं और इस धन का भाग जनता के हाथ में रहना चाहिए। हमारे उद्यमों में कम से कम 51 प्रतिशत सरकारी इक्विटी प्रतिधारित करते हुए, मैं अपने विनिवेश कार्यक्रम में जनता की भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। यहां स्पष्ट रूप से मेरा यह कहना है कि बैंक तथा बीमा कंपनियों जैसे सरकारी क्षेत्र के उद्यम सरकारी क्षेत्र में ही रहेंगे। उन्हें विकसित होने तथा प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए पूंजी प्रोत्साहन सहित सभी प्रकार की सहायता दी जाएगी।

वित्तीय क्षेत्र

38. वित्तीय क्षेत्र किसी भी अर्थव्यवस्था की प्राण-शक्ति होता है। बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र के प्रति हमारी सरकार का रवैया, वित्तीय पहुंच का विस्तार करने और बाजारों की पैठ गहन करते समय सुदृढ़ पर्यवेक्षण और विनियमन सुनिश्चित करना रहा है। इस संतुलित तरीके की गुणवत्ता हालिया अनुभवों में प्रदर्शित हुई है, क्योंकि वैश्विक वित्तीय बाजारों में उथल-पुथल ने भारतीय बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र को अपेक्षाकृत अप्रभावित रखा है। लगभग चालीस वर्ष पहले 14 जुलाई, 1969 को हमारी बैंकिंग प्रणाली का राष्ट्रीयकरण करने का इंदिरा गांधी का साहसी निर्णय विगत कुछ महीनों में विवेकपूर्ण और दूरदर्शी साबित हुआ है, जो पहले कभी नहीं हुआ था। उनके तौर-तरीकों से हमें प्रेरणा मिलती रही है, भले ही हम इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा और नई प्रौद्योगिकी ला रहे हैं।

39. भारतीय सूचीबद्ध कंपनियों में औसत सरकारी निर्गम 15 प्रतिशत से कम है। गहन गैर-छलसाधनीय बाजारों के लिए अपेक्षाकृत अधिक और विविधीकृत शेयरधारिता की आवश्यकता है। यह शर्त एक समान रूप से निजी क्षेत्र तथा सूचीबद्ध सरकारी क्षेत्र की कंपनियों के लिए लागू होनी चाहिए। मैं चरणबद्ध तरीके से, सभी सूचीबद्ध कंपनियों के लिए गैर-प्रवर्तनकारी सरकारी शेयरधारिता की प्रारंभिक सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूँ।

40. हमारे जैसे देश के लिए, जहाँ अधिकांश भाग और क्षेत्र बैंकिंग सुविधा से रहित हैं, वहाँ स्थायी दीर्घावधिक समता-मूलक विकास के लिए वित्तीय समावेशन महत्वपूर्ण है। वित्तीय समावेशन अभियान के भाग के रूप में, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक 'शून्य' या बहुत ही कम न्यूनतम शेष वाले "नो फ्रिल्स" खाते खोलते रहे हैं।

अब तक, इन बैंकों ने 3.3 करोड़ ऐसे खाते खोले हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी शाखा प्राधिकृत करने की नीति में और अधिक ढील देने की घोषणा की है। अब अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को पूर्व अनुमोदन के बिना ही सूचित करके ऑफ साइट एटीएम खोलने की अनुमति दी गई है।

41. देश में बैंकिंग नेटवर्क के विस्तार के बावजूद, अब भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें या तो आवश्यकता से कम बैंक हैं या हैं ही नहीं। राज्य स्तरीय बैंकिंग समिति की उप-समिति ऐसे क्षेत्रों का पता लगाएगी और आगामी 3 वर्षों में इन सभी क्षेत्रों को बैंकिंग सुविधा मुहैया कराने के निमित्त कार्य योजना तैयार करेगी। मैं, देश के प्रत्येक बैंक रहित ब्लॉक में बैंकिंग सेवा के लिए कम से कम एक केन्द्र/बिजली केन्द्र की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु मौजूदा वर्ष के दौरान एक बारगी सहायता अनुदान के रूप में 100 करोड़ रूपए निर्धारित करने का प्रस्ताव करता हूँ।

42. सरकार ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना की है। यह बाजारों में प्रतिस्पर्धा का संवर्धन करने तथा उसे बनाए रखने, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने और प्रतिस्पर्धा को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाले प्रभावों को रोकने के लिए एक स्वायत्तशासी विनियामक निकाय है। उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक अपीलीय निकाय भी बनाया गया है।

43. प्रतिस्पर्धा के फायदे अब अधिकाधिक क्षेत्रों और उनके प्रयोक्ताओं तथा उपभोक्ताओं को मिलने चाहिए। अब हमारे लिए आपूर्ति की बाधाओं को दूर करने, उत्पादकता बढ़ाने, उपभोक्ताओं को आपूर्ति की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की लागत कम करने तथा गुणवत्ता बढ़ाने के निमित्त इन पहलुओं पर कार्य करने का समय आ गया है।

निवेश माहौल

44. निजी क्षेत्र का निवेश वैश्विक वृहत आर्थिक स्थितियों से प्रभावित हुआ है। हमारी सरकार ऐसा अनुकूल माहौल बनाने के लिए वचनबद्ध है, जिसमें प्रतिस्पर्धी निजी क्षेत्र बढ़ सकता है और राष्ट्र के आर्थिक विकास में अपनी उचित भूमिका निभा सकता है। वर्ष 2004 से 2008 तक भारत की वार्षिक 8.5 प्रतिशत की उच्च विकास दर का बहुत बड़ा भाग निजी निवेश से जुटाया गया था। मैं उद्योग और अपने गतिशील उद्यमी समुदाय के साथ मिलकर कार्य करने के लिए उत्सुक हूँ ताकि उनकी बाकी समस्याओं का समाधान किया जा सके।

समावेशी विकास की ओर

45. अध्यक्ष महोदया, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने विकास की प्रक्रिया को अधिक समावेशी बनाने के लिए नीतियों में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। इसमें कमजोर वर्गों को बुनियादी सुख-सुविधाएं तथा आजीविका के अवसर प्रदान करने की कानूनी गारंटी देकर हकदारी देना शामिल है। अब "आम आदमी" हमारे सभी कार्यक्रमों और स्कीमों का केन्द्र-बिन्दु है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एनआरईजीएस)

46. (i) यह सर्वविदित है कि फरवरी 2006 से पहली बार कार्यान्वित राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा) बेहद सफल रहा है। वर्ष 2008-09 के दौरान, नरेगा द्वारा 2007-08 में शामिल किए गए 3.39 करोड़ परिवारों की तुलना में, 4.47 करोड़ से भी अधिक परिवारों को रोजगार अवसर प्रदान किए गए। हम नरेगा के तहत हकदारी के रूप में प्रतिदिन 100 रुपये की वास्तविक मजदूरी देने के लिए वचनबद्ध हैं। नरेगा के अधीन आस्तियों की उत्पादकता एवं संसाधन बढ़ाने के लिए कृषि, वानिकी, जल संसाधन, भू-संसाधन और ग्रामीण सड़कों से संबंधित अन्य स्कीमों को एक केन्द्राभिमुख लाने की प्रक्रिया शुरू की गयी है। पहली अवस्था में, ऐसे केन्द्राभिमुख के लिए कुल 115 प्रायोगिक जिलों को चुना गया है। इन उपायों और केन्द्राभिमुखता के दिशानिर्देशों का ब्यौरा मेरे साथी, ग्रामीण विकास मंत्री द्वारा दिया जाएगा। मैं नरेगा के निमित्त वर्ष 2009-10 के लिए 39,100 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ। यह बजट अनुमान 2008-09 की तुलना में 144 प्रतिशत की वृद्धि का द्योतक है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए)

(ii) मुझे यह कहते हुए हर्ष हो रहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम संबंधी कार्य ईमानदारीपूर्वक शुरू किया गया है। यह सुनिश्चित करेगा कि ग्रामीण या शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाला प्रत्येक परिवार 3 रुपये प्रति किलो की दर से प्रति माह 25 किलो चावल या गेहूँ के लिए कानूनी रूप से हकदार होगा। सरकार सार्वजनिक परिचर्या तथा परामर्श के लिए बहुत जल्दी खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग की वेबसाइट पर खाद्य सुरक्षा विधेयक का मसौदा रखना चाहती है।

भारत निर्माण

(iii) भारत निर्माण, अपनी छह योजनाओं के साथ, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच अन्तर को पाटने तथा विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों का जीवन स्तर सुधारने की ओर एक महत्वपूर्ण पहल है। मैं भारत निर्माण के लिए 2008-09 के बजट अनुमान की तुलना में 2009-10 में 45 प्रतिशत अधिक आवंटन करने का प्रस्ताव करता हूँ। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भारत निर्माण के अंतर्गत इसके सफल कार्यक्रमों में से एक है। मैं इस कार्यक्रम के लिए यह आवंटन, बजट अनुमान 2008-09 की तुलना में 59 प्रतिशत बढ़ाकर 12,000 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव करता हूँ। मैं राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के लिए भी 7,000 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ। यह 2008-09 (ब. अ.) की तुलना में 27 प्रतिशत अधिक है।

(iv) इंदिरा आवास योजना के लिए बजट अनुमान 2009-10 में आवंटन को 63 प्रतिशत बढ़ाकर 8800 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है। ग्रामीण आवास निर्माण की गति में तेजी लाने के लिए, मैं वाणिज्यिक बैंकों के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में ऋण प्रदान करने में आयी कमी से राष्ट्रीय आवास बैंक में ग्रामीण आवास निधि के लिए 2000 करोड़ रुपये की राशि आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ। यह

ग्रामीण आवास के क्षेत्र में राष्ट्रीय आवास बोर्ड के संसाधन आधार को उनके पुनर्वित्तपोषण कार्यों के लिए मजबूती प्रदान करेगा।

प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना

(v) लगभग 44,000 ऐसे गांव हैं जिनमें अनुसूचित जातियों की जनसंख्या 50 प्रतिशत से अधिक है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना नामक एक नई योजना, 1,000 ऐसे गांवों के एकीकृत विकास के लिए, प्रायोगिक आधार पर आरंभ की जा रही है। मैं इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ। ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन योजनाओं के तहत प्रत्येक गांव आवंटन के अलावा, 10 लाख रुपये का अन्तराल निधि पोषण प्राप्त कर सकेगा। प्रायोगिक चरण के सफल कार्यान्वयन पर, आगामी वर्षों में इस योजना का विस्तार किया जाएगा।

कमजोर वर्गों का सशक्तीकरण

47. स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में सुव्यवस्थित किया जा रहा है ताकि यह 2014-15 तक सभी के लिए लागू हो और गरीबी उन्मूलन के दृष्टिकोण में ध्यान देकर समयबद्ध ढंग से पूरी की जा सके। महिला स्व-सहायता समूहों के निर्माण पर बल दिया जाएगा। वर्धित दर पर पूंजी सब्सिडी मुहैया कराने के अलावा, बैंकों से लिए गए एक लाख रुपये तक के ऋणों के लिए गरीब परिवारों को ब्याज सब्सिडी देने का भी प्रस्ताव है।

48. महिला स्व-सहायता समूह अभियान ग्रामीण क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परिवर्तन ला रहा है। आज लगभग 22 लाख ऐसे समूह बैंकों से संबद्ध हैं। हमारा लक्ष्य आगामी पांच वर्षों में भारत की सभी ग्रामीण महिलाओं के कम से कम 50 प्रतिशत स्व-सहायता समूहों के सदस्यों के रूप में पंजीकृत करना और इन स्व-सहायता समूहों को बैंकों से जोड़ना है।

49. राष्ट्रीय महिला कोष गरीब महिलाओं को ऋण सहायता या अतिरिक्त वित्तपोषण सुकर बनाने के लिए कार्य करता रहा है। उनके फायदे के लिए इसने अनेक नवीन योजनाएं बनायी हैं। सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन और विकास के साधन के रूप में इस कोष की वर्तमान 100 करोड़ रुपये की मूल निधि को आगामी पांच वर्षों में बढ़ाकर 500 करोड़ रुपये कर दिया जाएगा।

महिला साक्षरता

50. महिला साक्षरता का निम्न स्तर गंभीर चिन्ता का विषय बना हुआ है। अतः राष्ट्रीय महिला साक्षरता मिशन आरंभ करने का निर्णय लिया गया है, जिससे अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य उपेक्षित वर्गों पर ध्यान दिया जा सके। इसका लक्ष्य तीन वर्षों में महिला साक्षरता के मौजूदा स्तर को कम करके आधा करना है।

एकीकृत बाल विकास सेवाएं

51. सरकार देश में एकीकृत बाल विकास सेवा स्कीम के सार्वभौमिकीकरण के लिए वचनबद्ध है। मार्च 2012 तक, एकीकृत बाल विकास सेवा स्कीम के अंतर्गत गुणवत्ता सहित सभी सेवाएं

छह वर्ष से कम आयु के प्रत्येक बच्चे को प्रदान की जाएगी।

कमजोर वर्ग के छात्रों को ऋण

52. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को उच्चतर शिक्षा हासिल करने में समर्थ बनाने के लिए, ऋण स्थगन अवधि के दौरान उन्हें पूरी ब्याज सब्सिडी मुहैया कराने की योजना शुरू करने का प्रस्ताव है। इसमें भारत में मान्यताप्राप्त संस्थानों से तकनीकी और व्यावसायिक क्षेत्रों में किसी भी अनुमोदित पाठ्यक्रम के अध्ययन हेतु ऐसे छात्रों द्वारा अनुसूचित बैंकों से लिए गए ऋण शामिल होंगे। अनुमान है कि इससे 5 लाख से अधिक छात्र लाभान्वित होंगे।

अल्पसंख्यक कल्याण

53. अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का आयोजना परिव्यय ब.अ. 2008-09 में 1000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2009-10 में 1740 करोड़ रुपए किया गया जो 74% अधिक है। इसमें चुनिंदा अपसंख्यक बहुल जिलों में अल्पसंख्यकों के लिए बहु-क्षेत्र विकास कार्यक्रम मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान को अनुदान-सहायता, जो प्रायः दोगुनी है और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम तथा अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिकपूर्व तथा मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों के प्रावधान हेतु 990 करोड़ रुपए शामिल हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप की नई स्कीमों तथा राज्य वक्फ बोर्डों के अभिलेखों के कम्प्यूटीकरण हेतु केन्द्रीय वक्फ परिषद् को सहायता-अनुदान देने के लिए भी आवंटन किए गए हैं।

54. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद तथा केरल में मल्लपुरम में अपने कैंपस स्थापित करने का निर्णय लिया है। मैं इन दोनों कैंपसों को 25-25 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ।

• असंगठित क्षेत्र में कामगारों का कल्याण

55. हमारी अर्थव्यवस्था का असंगठित अथवा अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगार का 92% हिस्सा है और यह हमारी श्रम शक्ति में होने वाली वार्षिक बढ़ोतरी का बड़ा हिस्सा है। असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा विधेयक, 2007 अब संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया जा चुका है। मैंने यह सुनिश्चित करने के लिए पहले ही कार्रवाई शुरू की है कि बुनकरों, मछुआरों तथा महिलाओं, ताड़ी निकालने वालों, चमड़ा तथा हस्तशिल्प कामगारों, बागान मजदूरों, निर्माण कार्य में लगे मजदूरों, खनन में लगे मजदूरों, बीड़ी कामगारों तथा रिक्शा चालकों जैसे रोजगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएं शीघ्रतिशीघ्र क्रियान्वित की जाएं। इन योजनाओं के लिए आवश्यक वित्तीय आवंटन किया जाएगा।

रोजगार कार्यालय

56. मैं सरकारी निजी भागीदारी में रोजगार कार्यालयों के आधुनिकीकरण की एक नई परियोजना शुरू करने का प्रस्ताव

करता हूँ ताकि रोजगार चाहने वाला कहीं से भी ऑन लाइन पंजीकरण कर सके तथा किसी भी रोजगार कार्यालय से संपर्क कर सके। इस परियोजना के तहत, साझा सॉफ्टवेयर के साथ एक राष्ट्रीय वेब पोर्टल विकसित किया जाएगा। इसमें एक ओर कुशल व्यक्तियों की उपलब्धता के संबंध में, वही दूसरी ओर उद्योग के पास कुशल व्यक्तियों की मांग संबंधी संपूर्ण डाटा होगा। इससे युवकों को रोजगार पाने में मदद मिलेगी और उद्योग वास्तविक समय आधार पर जरूरी कुशल कारीगर प्राप्त कर सकेगा।

हथकरघा

57. पिछले बजट में वाराणसी तथा शिवसागर में एक-एक क्लस्टर मेगा हथकरघा समूह और इरोड तथा भिवंडी में एक-एक मेगा बिजली करघा क्लस्टर अनुमोदित किए गए थे। इनका सफलतापूर्वक क्रियान्वयन हो रहा है। मैं पश्चिम बंगाल तथा तमिलनाडु में एक-एक हथकरघा मेगा समूह और राजस्थान में एक बिजली करघा मेगा समूह स्थापित करने का प्रस्ताव करता हूँ। इनसे पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में वस्त्र उद्योग की शानदार परंपरा बनाए रखने तथा राजस्थान में हजारों रोजगार सृजित करने में मदद मिलेगी। इसके अतिरिक्त, मैं श्रीनगर (जम्मू-कश्मीर) तथा मिर्जापुर (उत्तरप्रदेश) में कालीन उद्योग के लिए नए मेगा क्लस्टर स्थापित करने का प्रस्ताव करता हूँ।

स्वास्थ्य

58. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन सभी के लिए स्वास्थ्य का हमारा लक्ष्य हासिल करने का जरूरी साधन है। मैं अन्तरिम बजट में मुहैया कराए गए 12,070 करोड़ रुपए के अलावा 2,057 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव करता हूँ।

59. राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना पिछले वर्ष क्रियान्वित की गयी थी। आरंभिक अनुक्रियाएं बढ़ी अच्छी रही हैं। 18 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के 46 लाख से अधिक बीपीएल परिवारों को बायोमेट्रिक स्मार्ट कार्ड जारी किए गए हैं। इस योजना से गरीब परिवार निजी अस्पतालों सहित अस्पतालों की विस्तृत सूची में से स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ हासिल करने के लिए अपनी पसंद का अस्पताल चुनने के लिए स्वतंत्र हो सकेंगे। सरकार सभी बीपीएल परिवारों को इस स्कीम के तहत लाने का प्रस्ताव करती है। पिछले आवंटन की अपेक्षा 40% की बढ़ोतरी करते हुए बजट अनुमान 2009-10 में 350 करोड़ रुपए की राशि मुहैया की जा रही है।

पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन

60. पिछले वर्ष जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना प्रारंभ हुई थी। इसमें जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बनने तथा हमारे विकास के पथ की पारिस्थितिकीय टिकाऊपन बढ़ाने की हमारी कार्यनीति की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है इसके अनुसरण में आठ राष्ट्रीय मिशनों की शुरुआत की जा रही है जिनमें बहु-आयामी, दीर्घावधिक तथा एकीकृत दृष्टिकोण होगा।

61. हमारी सरकार "राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण" पहले ही स्थापित कर चुकी है। मैं राष्ट्रीय नदी और झील संरक्षण योजनाओं के लिए, 2008-09 में किए गए 335 करोड़ रुपये के आबंटन को बढ़ाकर 2009-10 में 562 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव करता हूँ।

62. मैं भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद्, देहरादून को उनके द्वारा अनुसंधान, शिक्षा तथा विस्तार के क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट कार्य को स्वीकारते हुए, 100 करोड़ रुपये का विशेष एकबारगी अनुदान देने का प्रस्ताव करता हूँ। मैं भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण तथा भारतीय जीव विज्ञान सर्वेक्षण के लिए 15-15 करोड़ रुपये का भी प्रस्ताव करता हूँ। भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण के लिए 15 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि का आबंटन किया जा रहा है।

जवाबदेह संस्थाओं के निर्माण की ओर

सार्वजनिक सेवाओं के वितरण में सुधार

63. अर्थव्यवस्था के विकास को गति देने तथा उसे अधिक समावेशी बनाने के लिए, सरकारी और निजी दोनों महत्वपूर्ण संसाधन जुटाए जाते हैं। इनका कार्यक्रम वितरण सरकारी कार्यक्रमों का केंद्र बिन्दु होना चाहिए। केंद्र तथा कई राज्यों में सूचना अधिकार अधिनियम का अधिनियमन इस दिशा में महत्वपूर्ण और सफल कदम रहा है। इससे सार्वजनिक निर्णय लेने की प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता तथा जवाबदेही सुनिश्चित करने की शुरुआत हुई है।

64. भारतीय अनन्य पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) स्थापित करना, सार्वजनिक सेवाओं के वितरण के संबंध में अभिशासन बेहतर बनाने में एक बड़ा कदम है। यह परियोजना मेरे हृदय में वास करती है। यह जानकर मैं प्रसन्न हूँ कि यह परियोजना एक ऐसे युग की शुरुआत कर रही है जहाँ भारत में निजी क्षेत्र के शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति अत्यावश्यक राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी लेने के लिए आगे आ रहे हैं। यह प्राधिकरण भारतीय निवासियों की पहचान तथा बायोमेट्रिक विवरणों का एक ऑन लाईन डाटाबेस स्थापित करेगा और देशभर में नामांकन और सत्यापन सेवाएं मुहैया कराएगा। अनन्य पहचान संस्थाओं की प्रथम श्रृंखला 12 से 18 महीनों में तैयार होगी। मैंने इस परियोजना के लिए 120 करोड़ रुपये के प्रावधान का प्रस्ताव किया है।

राष्ट्रीय सुरक्षा

65. राज्यों में पुलिस तंत्र को मजबूत करने के लिए अंतरिम बजट में किए गए 430 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि का प्रस्ताव किया जा रहा है। सरकार ने अर्ध सैनिक बलों के कर्मियों के लिए रक्षा बलों के समतुल्य विशेष जोखिम/कठिनाई भत्ता भी स्वीकृत किया है। इन भत्तों के भुगतान संबंधी प्रावधान भी बजट में प्रस्तावित किए जा रहे हैं।

66. सीमा प्रबंधन सुदृढ़ करने के लिए अंतरिम बजट में किए गए प्रावधानों के अलावा, 2,284 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि

अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर बाड़, सड़कें, फ्लड लाइटों के निर्माण हेतु प्रदान की जा रही हैं।

67. अर्ध सैनिक बलों की संख्या में काफी बढ़ोतरी की जा रही है। इसके लिए, खास तौर पर आवास के क्षेत्र में आवश्यक आधारभूत संरचना सृजित करने में अधिक निवेश की जरूरत होगी। इसलिए सरकार केन्द्रीय अर्ध सैनिक बल कर्मियों के लिए 1 लाख निवास इकाइयों के सृजन के लिए आवास निर्माण का एक व्यापक कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव करती है। इससे न केवल इन बलों का मनोबल बढ़ेगा, बल्कि सरकार के वार्षिक बजटीय साधन भी बढ़ेंगे तथा एक नवीन वित्तपोषण मॉडल तैयार होगा।

भूतपूर्व सैनिकों के लिए एक रैंक एक पेंशन (ओआरओपी)

68. हमारा देश अपने बहादुर भूतपूर्व सैनिकों की कृतज्ञता का बहुत ऋणी है। मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता वाली ओआरओपी संबंधी समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है और इस समिति द्वारा की गई सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं। इन सिफारिशों के आधार पर, सरकार ने आफिसर रैंक से नीचे (पीबीओआर) के रक्षा पेंशनरों की 1-1-2006 से पूर्व की पेंशन में पर्याप्त सुधार करने और 10-10-1997 से पहले के पेंशनरों को 10-10-1997 के बाद पेंशनरों के समकक्ष लाने का निर्णय लिया है। इन दोनों निर्णयों को 1 जुलाई, 2009 से कार्यान्वित किया जाएगा। जिसके फलस्वरूप 12 लाख से अधिक जवानों और जेसीओ की पेंशन बढ़ जाएगी। इन उपायों से राजकोष पर 2100 करोड़ रुपये से अधिक का वार्षिक भार पड़ेगा। उदारीकृत पेंशन लाभों को युद्ध में घायल और अन्य विकलांग पेंशनरों को दिए जा रहे कतिपय पेंशन लाभों को भी उदारीकृत किया जा रहा है।

शिक्षा

69. भारत का जनसांख्यिकीय लाभ नौजवान लोगों के एक बड़े हिस्से के रूप में है जिसे उचित शिक्षा तथा दक्षता उपलब्ध कराकर गतिशील आर्थिक लाभ में परिणत किए जाने की आवश्यकता है। 'आईसीटी के जरिए शिक्षा मिशन' नामक योजना में प्रावधान को पर्याप्त रूप से बढ़ाकर 900 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इसी प्रकार, दक्षता विकास मिशन के अन्तर्गत पोलिटेक्निकों की स्थापना तथा उन्नयन के लिए प्रावधान को बढ़ाकर 495 करोड़ रुपये किया गया है। सरकार कवर न किए गए प्रत्येक राज्य में एक केन्द्रीय विश्व-विद्यालय स्थापित करने की अपनी मंशा को आगे बढ़ाएगी। इस प्रयोजनार्थ, मैं 827 करोड़ रुपये का आवंटन कर रहा हूँ। मैं आईआईटी और एनआईटी के लिए भी 2113 करोड़ रुपये का आवंटन कर रहा हूँ जिसमें नए आईआईटी तथा एनआईटी के लिए 450 करोड़ रुपये का प्रावधान शामिल है। उच्च शिक्षा हेतु समग्र आयोजना बजट को अन्तरिम ब.अ. के तुलना में 2000 करोड़ रुपये तक बढ़ाने का प्रस्ताव है।

70. चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र पंजाब तथा हरियाणा की राजधानी है। पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ में सुविधाओं में सुधार की जरूरत है। इसलिए मैं इस विश्वविद्यालय हेतु 50 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव करता हूँ। लोगों को बेहतर आधारभूत संरचना उपलब्ध

कराने हेतु संघ राज्य प्रशासन को सक्षम बनाने के लिए, मैं मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान चंडीगढ़ हेतु आयोजना आवंटन में यथोचित वृद्धि का प्रस्ताव करता हूँ।

राष्ट्र मंडल खेल 2010

71. राष्ट्र मंडल खेल देश को एक उभरती एशियाई शक्ति के रूप में हमारी क्षमता को प्रदर्शित करने का अवसर प्रस्तुत करते हैं। मैं राष्ट्रमण्डल खेलों के लिए अन्तरिम बजट में किए गए 2112 करोड़ रुपये के बजट आवंटन को काफी बढ़ाकर बजट 2009-10 में 3472 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव करता हूँ।

72. अध्यक्ष महोदया, सरकार श्रीलंका के तमिलों को श्रीलंका की प्रादेशिक सम्प्रभुता और उसके संविधान के अन्तर्गत उनके अधिकारों और वैध आकांक्षाओं को सुनिश्चित करने के प्रति वचनबद्ध है। विदेश मंत्रालय श्रीलंका सरकार के साथ इस सम्बन्ध में निकट सम्पर्क बनाए हुए है। मैं आन्तरिक रूप से विस्थापित लोगों के पुनर्वास और श्रीलंका के उत्तरी तथा पूर्वी क्षेत्रों के पुनर्निर्माण हेतु 500 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ।

73. जैसाकि माननीय सदस्यों को ज्ञात ही है, मई, 2009 के अंतिम सप्ताह में आए पश्चिम बंगाल के तट पर भीषण चक्रवात आइला से सड़कों, घरों और आधारभूत संरचना को भारी नुकसान पहुंचा। आपदा राहत निधि (सीआरएफ) से जहाँ तुरन्त अन्तरिम राहत उपलब्ध करायी गयी, वहीं क्षतिग्रस्त आधारभूत संरचना के पुनर्निर्माण का कार्यक्रम भी तैयार करना प्रस्तावित है। इस प्रयोजनार्थ, मैं 1,000 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव करता हूँ।

बजट अनुमान 2009-10

अध्यक्ष महोदया, अब मैं वर्ष 2009-10 के बजट अनुमानों पर प्रकाश डालता हूँ।

74. बजट अनुमान 2009-10 में 10,20,838 करोड़ रुपये के कुल व्यय की व्यवस्था है जिसमें 6,95,689 करोड़ रुपये का आयोजना-भिन्न व्यय और 3,25,149 करोड़ रुपये का आयोजना व्यय शामिल है। ब.अ. 2008-09 की तुलना में आयोजना-भिन्न व्यय में 37 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है जबकि आयोजना व्यय में 34 प्रतिशत की वृद्धि हुई। ब.अ. 2008-09 की तुलना में वर्ष 2009-10 में व्यय में कुल वृद्धि 36 प्रतिशत हुई।

75. आयोजना-भिन्न व्यय में बढ़ोतरी का मुख्य कारण छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन, वर्धित खाद्य सब्सिडी और वर्ष 2008-09 में अधिक राजकोषीय घाटे की वजह से उच्च ब्याज अदायगी का होना है। ब्याज अदायगियां 2,25,511 करोड़ रुपये अनुमानित हैं जो ब.अ. 2009-10 में आयोजना-भिन्न राजस्व का लगभग 36 प्रतिशत होती हैं। सब्सिडियों के लिए कुल प्रावधान ब.अ. 2008-09 में 71,431 करोड़ रुपये से बढ़कर ब.अ. 2009-10 में 1,11,276 करोड़ रुपये हो गया। रक्षा परिव्यय ब.अ. 2008-09 में 1,05,600 करोड़ रुपये से बढ़कर ब.अ. 2009-10 में 1,41,703 करोड़ रुपये हो गया।

76. माननीय सदस्यों को याद होगा कि मैंने 2009-10 का अन्तरिम बजट पेश करते समय यह कहा था कि वर्ष 2009-10 के लिए आयोजना व्यय में वैश्विक मंदी तथा आर्थिक मंदी के प्रभाव को कम करने हेतु प्रतिचक्र्रीय उपायों के भाग के रूप में और बढ़ोतरी करनी पड़ सकती है। सेनवैट तथा सेवा कर दरों में कटौती के कारण सीमित राजकोषीय गुंजाइश की पृष्ठभूमि के मुकाबले सरकार ने वार्षिक आयोजना 2009-10 के लिए सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) को, 2009-10 के अन्तरिम बजट की तुलना में 40,000 करोड़ रुपये तक बढ़ाने का सुविचारित तथा साहसिक निर्णय लिया है। इस वर्धित जीबीएस की बड़ी राशि का अधिकांश हिस्सा आधारभूत संरचना में सार्वजनिक निवेश के लिए निर्दिष्ट है, जिसमें विकास सम्भावना को बढ़ाकर और आय-सृजन की तरफ बढ़ते हुए ग्रामीण आधारभूत संरचना पर विशेष बल दिया जाता है। इसके अलावा, राज्य सरकारों को एफआरबीएम के अन्तर्गत उनके जीएसडीपी के 3.5 प्रतिशत से 4 प्रतिशत तक राजकोषीय घाटा लक्ष्यों में छूट देकर उनके जीएसडीपी के 0.5 प्रतिशत अतिरिक्त उधार लेने की अनुमति प्रदान की जाएगी। इससे राज्य सरकारें मौजूदा वर्ष में लगभग 21,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त मुक्त बाजार ऋण जुटाने में सक्षम होंगी। दूसरे शब्दों में, केन्द्र तथा राज्यों का संयुक्त कुल अतिरिक्त आयोजना व्यय, अन्तरिम बजट की अपेक्षा 61,000 करोड़ रुपये होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि यह राजकोषीय विस्तार आगे चलकर आर्थिक मंदी के प्रभाव को उलट देगा और मध्यावधि में हमारी विकास वृद्धि की बहाली में तेजी लाएगा।

77. अध्यक्ष महोदया, मौजूदा वर्ष में आर्थिक मंदी के बने रहने की सम्भावना को देखते हुए, सकल कर प्राप्तियां ब.अ. 2009-10 में 6,41,079 करोड़ रुपये होने का अनुमान है जबकि ब.अ. 2008-09 में ये 6,87,715 करोड़ रुपये थीं। तथापि, कर-भिन्न राजस्व प्राप्तियों के बेहतर होने का अनुमान है जो ब.अ. 2008-09 में 95,785 करोड़ रुपये की तुलना में ब.अ. 2009-10 में 1,40,279 करोड़ रुपये अनुमानित हैं। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजस्व घाटा, ब.अ. 2008-09 में 1 प्रतिशत की तुलना में 4.8 प्रतिशत अनुमानित है और 2008-09 के अनन्तिम लेखाओं के अनुसार यह 4.6 प्रतिशत है। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा ब.अ. 2008-09 में 2.5 प्रतिशत की तुलना में 6.8 प्रतिशत अनुमानित है और 2008-09 के अनन्तिम लेखाओं के अनुसार 6.2 प्रतिशत है। घाटे का यह स्तर चिन्ता का विषय है। सरकार यथा सम्भव राजकोषीय समेकन के रास्ते पर वापस आने के लिए इस मुद्दे का पूरी ईमानदारी से समाधान खोजेगी।

78. अध्यक्ष महोदया, अपने कर प्रस्तावों की तरफ बढ़ने से पहले, मैं कौटिल्य का उल्लेख करने का लोभ-संवरण नहीं कर सकता। उनके कथन को मैं यहां उद्धृत करना चाहूँगा "जिस प्रकार कोई व्यक्ति बगीचे से पके फलों को तोड़ता है, उसी प्रकार एक राजा सभी राजस्व संग्रहित करता है, जब वह देय हो जाता है। जिस प्रकार कोई बिना पके फलों को एकत्र नहीं करता, उसी प्रकार राजा देय न हुए धन को लेने से बचेगा क्योंकि ऐसा न करने पर लोग क्रोधित होंगे और राजस्व के स्रोत को ही नष्ट कर देंगे।"

भाग-ख

कर प्रस्ताव

79. अध्यक्ष महोदया, मैं अब अपने कर प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ।

80. जैसा कि सदन को ज्ञात है, इस सरकार के पिछले कार्यकाल सहित, विगत कुछ वर्षों के दौरान सुधारों का जोर हमारी कर प्रणाली की कार्यक्षमता और साम्या में सुधार लाने पर रहा है। कर ढांचे की विसंगतियों को दूर करके, कराधान के संतुलित स्तर लागू करके और कराधार का विस्तार करके इसे प्राप्त करने का प्रयास किया गया है। इन नीतिगत परिवर्तनों के साथ-साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर दोनों के लिए, स्वचालन प्रणाली अपनाने सहित प्रमुख व्यावसायिक प्रक्रियाओं की वांछित री-इंजनीयरिंग की गई है। प्रत्यक्ष कर के क्षेत्र में, कार्यक्षमता में और अधिक सुधार लाने के लिए हाल ही में बेंगलुरु में एक केन्द्रीयकृत प्रोसेसिंग सेन्टर (सीपीसी) की स्थापना करने की पहल की गई है। इस केन्द्र में इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल की गई सभी विवरणियों और सम्पूर्ण कर्नाटक में दाखिल की गई कागजी विवरणियों पर कार्रवाई की जाएगी।

81. इन कर सुधार संबंधी प्रयासों से प्रभावशाली परिणाम मिले हैं। केन्द्र का कर-सकल घरेलू उत्पाद अनुपात 2003-04 में 9.2 प्रतिशत के निम्न स्तर से बढ़ कर 2008-09 में 11.5 प्रतिशत हो गया है। पिछले पांच वर्षों के दौरान कर राजस्व में इस प्रभावशाली वृद्धि का कारण वस्तुतः प्रत्यक्ष करों में वृद्धि है। इसके अतिरिक्त, केन्द्र के कर-राजस्व में प्रत्यक्ष करों का हिस्सा 2003-04 में 41 प्रतिशत से बढ़कर 2008-09 में 56 प्रतिशत हो गया है, जो हमारी कर प्रणाली की साम्या में तीव्र सुधार को परिलक्षित करता है। सरकार कर सुधारों की इस प्रक्रिया को और आगे बढ़ाने के प्रति वचनबद्ध है।

82. इस बजट को तैयार करने की अवधि में, मुझे बड़ी संख्या में पण्यधारियों (स्टेकहोल्डरों) से संवाद करने और उनसे बहुमूल्य विचार प्राप्त करने का अवसर मिला। अधिकांश सुझाव कर प्रणाली में ढांचागत परिवर्तनों के संबंध में थे। सभी सुधारों की तरह, कर सुधार एक प्रक्रिया है, न कि एक घटना। अतः मैं प्रत्यक्ष करों के संबंध में आगामी 45 दिन के भीतर नया प्रत्यक्ष कर कोड जारी करके और अप्रत्यक्ष करों के संबंध में, 1 अप्रैल 2010 से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की सुचारू शुरुआत करने की प्रक्रिया में तेजी लाकर ढांचागत परिवर्तनों को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूँ।

83. प्रत्यक्ष कर कोड, एक परिचर्चा दस्तावेज सहित, आम जनता में बहस के लिए जारी किया जाएगा। प्राप्त विचारों के आधार पर, सरकार प्रत्यक्ष कर कोड विधेयक को अन्तिम रूप देगी ताकि उसे शीतकालीन अधिवेशन के दौरान किसी समय इस सदन में प्रस्तुत किया जा सके।

84. कर प्रशासन की कार्यक्षमता और अधिक बढ़ाने के लिए, मेरा संगत अधिनियमों में संशोधन करके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर संबंधी अग्रिम विनिर्णय के दो प्राधिकरणों का विलय करने का इरादा है। इससे आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 245-ए के अधीन

गठित अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण अप्रत्यक्ष करों के लिए अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण के रूप में भी कार्य कर सकेगा।

85. मुझे बताया गया है कि राज्य वित्त मंत्रियों की सशक्त समिति ने वस्तु एवं सेवा कर की कार्ययोजना और संरचना तैयार करने में काफी प्रगति की है। केन्द्र सरकार के अधिकारियों को भी इस कवायद में सहयोजित किया गया है। मुझे सदन को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि अपने मिले-जुले प्रयासों से वे संविधान में प्रतिष्ठापित राजकोषीय संघीय व्यवस्था के सिद्धान्तों के अनुरूप इसके मूल ढांचे पर एक सहमति पर पहुंच चुके हैं। मैं राज्य वित्त मंत्रियों की सशक्त समिति का उनके अथक प्रयासों के लिए अभिनन्दन करता हूँ। वस्तु एवं सेवा कर माडल की मोटे तौर पर रूपरेखा यह है कि यह एक दोहरा वस्तु एवं सेवा कर होगा, जिसमें एक केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर और एक राज्य वस्तु एवं सेवा कर शामिल होगा। केन्द्र और राज्य क्रमशः केन्द्रीय जीएसटी और राज्य जीएसटी के संबंध में कानून बनाएंगे, उद्ग्रहण करेंगे और उन्हें प्रशासित करेंगे। मैं सभी पण्यधारियों के साथ विधिवत परामर्श के बाद 1 अप्रैल 2010 तक वस्तु एवं सेवाकर लागू करने को सुविधाजनक बनाने हेतु केन्द्र सरकार की उत्प्रेरक भूमिका को और सशक्त बनाऊंगा।

प्रत्यक्ष कर

86. मैं, अब प्रत्यक्ष करों पर आता हूँ।

87. अध्यक्ष महोदया, कारपोरेट सेक्टर से कर दरों में कमी की मांगें उठती रही हैं। तथापि कर दरें कराधार के आकार द्वारा, निर्धारित की जाती हैं; यदि कराधार उच्च है तो कर दरें न्यून हो सकती हैं। आयकर अधिनियम में बहुविध कर छूटों की भरमार है जिससे कराधार में बहुत हद तक कमी आ जाती है। इस क्षरण की सीमा को परित्यक्त राजस्व विवरणी के रूप में इस सदन में प्रस्तुत किया जाता है। प्रत्यक्ष कर राजस्व में वृद्धि की अपेक्षा, परित्यक्त प्रत्यक्ष कर राजस्व में वृद्धि सापेक्षिक रूप से अधिक है। तदनुसार, मेरा कारपोरेट कर दरों में किसी प्रकार के परिवर्तन का प्रस्ताव नहीं है।

88. छोटे और सीमान्त करदाताओं और वरिष्ठ नागरिकों को अन्तरिम राहत प्रदान करने की दृष्टि से, मैं वरिष्ठ नागरिकों के लिए वैयक्तिक आय कर की छूट की सीमा 15,000 रुपये बढ़ाकर 2.25 लाख रुपये से 2.40 लाख रुपये करने का प्रस्ताव करता हूँ इसी प्रकार, मैं महिला करदाताओं के लिए यह छूट सीमा 10,000 रुपये बढ़ाकर 1.80 लाख रुपये से 1.90 लाख रुपये और व्यक्ति करदाताओं की अन्य सभी श्रेणियों के लिए 10,000 रुपये बढ़ाकर 1.50 लाख रुपये से 1.60 लाख रुपये करने का भी प्रस्ताव करता हूँ। इसके अलावा, मैं गंभीर निःशक्तताग्रस्त आश्रित व्यक्ति की चिकित्सा परिचर्या, सहित भरण-पोषण के संबंध में धारा 80-घघ के अधीन कटौती को भी 75,000 रुपये की वर्तमान सीमा से बढ़ाकर 1 लाख रुपये करने का प्रस्ताव करता हूँ।

89. विगत में, आमतौर पर प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न होने वाली राजस्व संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रत्यक्ष करों पर अधिभार लगाए जाते रहे हैं। सरकार ने आपात स्थितियों से निपटने के लिए संसाधनों के निर्माण हेतु प्राकृतिक आपदा

निधि की स्थापना की। इसके परिणामस्वरूप, प्रत्यक्ष करों पर अधिभार हटाया जाना चाहिए। तथापि, इसे सरकार की राजस्व संबंधी आवश्यकताओं के साथ संतुलित किए जाने की आवश्यकता है। अतः प्रथमतया, मैं वैयक्तिक आय-कर पर 10 प्रतिशत का अधिभार समाप्त करके विभिन्न प्रत्यक्ष करों पर अधिभार को क्रमिक रूप से समाप्त करने का प्रस्ताव करता हूँ।

90. आय-कर अधिनियम की धारा 10क और 10ख के अन्तर्गत निर्यात लाभों के सम्बन्ध में कटौती उपलब्ध है। इन धाराओं के अन्तर्गत कटौती वित्त वर्ष 2009-10 से आगे उपलब्ध नहीं होगी। निर्यात में मंदी का सामना करने के लिए, मैं इन करावकाशों के सम्बन्ध में सीमान्त खण्डों को एक और वर्ष यानी वित्त वर्ष 2010-11 के लिए विस्तारित करने का प्रस्ताव करता हूँ।

91. वित्त अधिनियम, 2005 में अनुषंगी लाभ कर की शुरुआत की गयी थी जो नियोक्ताओं द्वारा अपने कर्मचारियों को उपलब्ध कराए गए कतिपय अनुषंगी लाभों के मूल्य से सम्बद्ध है। इस कर को पर्याप्त अनुपालना भार-लादने के रूप में समझा गया है। इन भावनाओं के प्रति सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए, मैं अनुषंगी लाभ कर को समाप्त करने का प्रस्ताव करता हूँ।

92. किसी अर्थव्यवस्था की प्रतिस्पर्द्धी क्षमता अनुसंधान तथा विकास (आर. एंड डी) के क्षेत्र में इसकी प्रगति पर निर्भर करती है। आर एंड डी कार्य निष्पादित करने हेतु कारपोरेट क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए, मैं एक लघु निषेध सूची को छोड़कर, सभी विनिर्माण व्यवसायों के सम्बन्ध में आन्तरिक अनुसंधान तथा विकास पर होने वाले व्यय पर 150 प्रतिशत की भारित कटौती के मौजूदा प्रावधान की सीमा का विस्तार करने का प्रस्ताव करता हूँ।

93. आयकर अधिनियम की मौजूदा योजना के अन्तर्गत, कर छूटें अधिकांशतः लाभ से सम्बद्ध हैं। ऐसे प्रोत्साहन स्वभावतः अक्षम और दुरुपयोग का कारण हैं। इसलिए, निवेश सम्बद्ध कर छूटें उपलब्ध कराकर व्यवसायों को प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव है। इसको शुरू करने हेतु, मैं व्यवसायों के सम्बन्ध में निवेश सम्बद्ध कर प्रोत्साहनों को विस्तारित करने का प्रस्ताव करता हूँ जो 'कोल्ड चैन' की स्थापना और संचालन, कृषि उपज के भंडारण हेतु भाण्डागार सुविधाएं तथा सामान्य वाहक सिद्धान्त पर वितरण हेतु सम्पूर्ण देश में प्राकृतिक गैस अथवा कच्चे अथवा पैट्रोलियम तेल पाइपलाइन नेटवर्क स्थापित करने और उसे संचालित करने से सम्बद्ध होगा। इस विधि के तहत, भूमि सदाशयता तथा वित्तीय लिखतों पर होने वाले व्यय को छोड़कर सभी पूंजीगत व्यय पूर्णतः कटौती रूप से अनुमत होंगे।

94. न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) की शुरुआत कारपोरेट करदाताओं के कराधान में असमता को दूर करने हेतु की गयी थी। बेहतर समता की तलाश हेतु मैं मैट की दर में बढ़ोतरी करके बही लाभों की 10 प्रतिशत की मौजूदा दर को बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ। तथापि, कारपोरेट करदाताओं को राहत प्रदान करने हेतु, मैं मैट के अन्तर्गत कर ऋण की अग्रेनीत अनुमत सत्ता वर्षों की अवधि को बढ़ाकर दस वर्ष करने का भी प्रस्ताव करता हूँ।

95. नई पेंशन योजना (एनपीएस) भारत में टिकाऊ, सक्षम, स्वेच्छिक तथा परिभाषित अंशदान पेंशन प्रणाली के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। जबकि नई पेंशन योजना के अन्तर्गत बचतों पर निवेश और उस पर उपार्जित व्याज दो स्तरों पर कर छूट और आहरण के स्तर पर करारोपण (बचतों के कर संव्यवहार की ईईटी पद्धति) जारी रहेगी, वहीं दूसरी ओर प्रस्ताव है कि इस अति आवश्यक सुरक्षा प्रणाली की स्थापना हेतु एनपीएस को आवश्यक राजकोषीय सहायता उपलब्ध करायी जाए। तदनुसार, मैं एनपीएस ट्रस्ट की आय और लाभांश वितरण कर से इस ट्रस्ट को भुगतान किए जाने वाले किसी भी लाभांश को आयकर से छूट देने का प्रस्ताव करता हूँ। इसी प्रकार, एनपीएस ट्रस्ट द्वारा इक्विटी शेयरों तथा व्युत्पन्नों की सम्पत्ति खरीद तथा बिक्री को भी प्रतिभूति लेन-देन कर से छूट प्राप्त होगी। मैं यह भी प्रस्ताव करता हूँ कि स्व-नियोजित व्यक्ति एनपीएस में सहभागी बनें और तत्संबंधी उपलब्ध कर लाभों को प्राप्त करें।

96. देश में निवेश के माहौल में और सुधार के लिए, हमें विदेशी कम्पनियों द्वारा सामना किए जा रहे कर विवादों को एक उचित समय-सीमा के भीतर सुलझाने हेतु सुगम बनाने की आवश्यकता है। यह विशेष रूप से सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) क्षेत्र की कम्पनियों के लिए प्रासंगिक होगा। इसलिए, मैं अन्तरण मूल्य निर्धारण विवादों के समाधान हेतु आयकर विभाग के अन्तर्गत एक वैकल्पिक विवाद निपटान तंत्र की स्थापना का प्रस्ताव करता हूँ। अन्तरराष्ट्रीय लेन-देनों में अन्तरण मूल्यों के निर्धारण में न्यायिक भूलों के प्रभाव को कम करने के लिए, यह प्रस्ताव है कि केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) को 'सेफ हार्बर' नियमों को तैयार करने के लिए सशक्त बनाया जाए।

97. वित्त अधिनियम, 2008 ने वस्तु लेन-देन कर (सीटीटी) की शुरुआत की जो मान्यताप्राप्त एसोसिएशन में दर्ज कर योग्य वस्तुओं के लेन-देन में लगाया जाता है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद् ने सीटीटी को समाप्त करने की सिफारिश की है। इसलिए मैं वस्तु लेन-देन कर को समाप्त करने का प्रस्ताव करता हूँ।

98. सदन इस बात से सहमत होगा कि देश में राजनीतिक दलों के वित्तपोषण में पारदर्शिता लाना बांछनीय है। राजनीतिक दलों के वित्तपोषण की व्यवस्था में सुधार लाने की दृष्टि से, मैं यह प्रस्ताव करता हूँ कि निर्वाचन ट्रस्टों में दिए गए दान को दानकर्ता की आय की संगणना में 100 प्रतिशत की कटौती के रूप में अनुमति दी जाएगी। इस प्रयोजनार्थ निर्वाचन ट्रस्ट ऐसे ट्रस्ट होंगे जिनकी स्थापना राजनीतिक दलों तक दान पहुंचाने में एक मध्यस्थ वाहक की भूमिका का निर्वहन करेगी तथा जिसे केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

99. आयकर अधिनियम की धारा 80ड में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में अध्ययन के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु ऋणों पर दिए जाने वाले व्याज के सम्बन्ध में कटौती की व्यवस्था है। मैं इस प्रस्ताव की सीमा को विस्तारित करने का प्रस्ताव करता हूँ ताकि स्कूली शिक्षा पूर्ण करने के बाद व्यावसायिक अध्ययनों सहित अध्ययन के सभी क्षेत्रों को शामिल किया जा सके।

100. धर्मार्थ संस्थाओं को दिए जाने वाले अनाम दान वर्तमान में कर योग्य हैं ताकि अनाम दान के रूप में ऐसी संस्थाओं में आने वाले लेखा-बाढ़ धन को रोका जा सके, तथापि कुछ संगठन प्रक्रियात्मक शर्तों का अनुपालन करने में वास्तविक समस्याओं का सामना कर रहे हैं। ऐसे धर्मार्थ संगठनों के समक्ष आ रही व्यावहारिक दिक्कतों को कम करने हेतु, मैं ऐसे संगठनों के अनाम दानों पर कर न लगाकर राहत प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूँ जो उनकी कुल आय की 5 प्रतिशत सीमा तक अथवा 1 लाख रुपये की राशि, जो भी अधिक हो, के अंतर्गत हो।

101. सभी लघु कर दाताओं के व्यावसायिक कार्यों में सुविधा के लिए तथा उनके अनुपालन भार को कम करने हेतु मैं 40 लाख रुपये तक का कारोबार करने वाले समस्त लघु व्यवसायियों के संबंध में प्रकल्पित कराधान की सीमा को विस्तारित करने का प्रस्ताव करता हूँ। ऐसे सभी करदाताओं को अपने कारोबार के 8 प्रतिशत की दर पर व्यवसाय से अपनी आय घोषित करने का विकल्प होगा और इसके साथ ही वे लेखा-बहियां रखने के अनुपालन भार से छूट का फायदा उठा सकते हैं। प्रक्रिया संबंधी सरलीकरण के रूप में मैं उन्हें अग्रिम कर का भुगतान करने की छूट देते हुए अपनी विवरणी दर्ज कराते समय व्यवसाय से उनकी समूची कर देनदारी अदा करने की अनुमति का प्रस्ताव भी करता हूँ। यह नई योजना वित्त वर्ष 2010-11 से लागू होगी।

102. अध्यक्ष महोदया, भू-राजनीतिक माहौल के परिप्रेक्ष्य में हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम ऊर्जा संरक्षण की अपनी सुविधाएं सृजित करें। तदनुसार, मैं आयकर अधिनियम की धारा 80-इख(9) के अंतर्गत करावकाश जो अब तक वाणिज्यिक उत्पादन अथवा खनिज तेल के परिष्करण से उद्भूत लाभों के संबंध में उपलब्ध था, का विस्तार प्राकृतिक गैस के लिए भी करने का प्रस्ताव करता हूँ। यह कर लाभ तेल और गैस के ऐसे ब्लॉकों, जो नई उत्खनन लाइसेंसिंग नीति-बोलियों के VIII दौर के अंतर्गत दिए जाते हैं से खनिज तेल और प्राकृतिक गैस के वाणिज्यिक उत्पादन से व्युत्पन्न लाभों के संबंध में उपक्रमों के लिए उपलब्ध होंगे। इसके अतिरिक्त, मैं उक्त धारा के उपबंधों में यह व्यवस्था करने के लिए भी भूतलक्षी प्रभाव से संशोधन करने का प्रस्ताव करता हूँ कि धारा 80-इख(9) के प्रयोजनों हेतु "अंडरटेकिंग" से अभिप्राय होगा किसी एकल सौविदा में प्रदत्त सभी ब्लॉक।

103. आयकर अधिनियम की धारा 2(15) के वर्तमान उपबंधों के अंतर्गत, "पुण्यार्थ प्रयोजन" में निर्धन को राहत, शिक्षा, चिकित्सा राहत और "सामान्य जनोपयोगी किसी अन्य प्रयोजन को बढ़ावा देने" के लिए राहत शामिल है। तथापि "सामान्य जनोपयोगी किसी अन्य प्रयोजन को बढ़ावा देने" में व्यापार, वाणिज्य के कारोबार की प्रकृति के किसी क्रियाकलाप का निष्पादन शामिल नहीं होगा। मैं हमारे पर्यावरण (जलसंभरण, वन और वन्य जीव सहित) के परिक्षण और सुधार तथा हमारे स्मारकों अथवा स्थलों या शिल्प अथवा ऐतिहासिक महत्व की वस्तुओं के परिरक्षण में लगे हुए न्यासों को वही कर व्यवहार उपलब्ध कराने का प्रस्ताव करता हूँ जो निर्धन को राहत, शिक्षा और चिकित्सा राहत प्रदान कराने में लगे न्यासों को उपलब्ध है।

अप्रत्यक्ष कर

104. अध्यक्ष महोदया, मैं अप्रत्यक्ष करों के संबंध में अपने मुख्य प्रस्तावों की ओर आता हूँ।

105. मैं पहले सीमा शुल्कों का उल्लेख करूंगा।

106. यद्यपि हमारे घरेलू उद्योग ने वैश्विक वित्तीय संकट से उत्पन्न मंदी के प्रभाव को समुत्थान शक्ति से कम कर दिया है, परन्तु इससे अभी पूरी तरह उबरना शेष है। विनिर्माण वृद्धि जो अक्टूबर 2008 में वर्षानुवर्ष आधार पर ऋणात्मक हो गई थी और इस वर्ष मार्च तक ऐसी ही बनी रही, लगता है इसमें अब थोड़ा सुधार आ रहा है। हालांकि, वैश्विक परिदृश्य चिन्ताजनक बना हुआ है और मेरा यह विचार है कि उद्योग को स्थिर ढांचा उपलब्ध कराए जाने की सर्वोपरि आवश्यकता है। अप्रत्यक्ष करों संबंधी मेरे प्रस्तावों में सीमा-शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्कों के साथ-साथ सेवा कर के समग्र कर ढांचे को बनाए रख कर इसे प्राप्त करने का प्रयास है। मैं यह अवश्य बताना चाहूंगा कि मैं मिथ्यावर्णनों से उत्पन्न किसी बाध्यकारी कारण के संबंध में कार्रवाई करने में, अथवा कष्ट निवारण के लिए राहत देने में तनिक भी हिचका नहीं हूँ।

107. कंडिशनल एक्सेस सिस्टम के सुचारू आरंभ के लिए उनका मुक्त आयात करते हुए 2006 में सेट टाप बाक्स को बुनियादी सीमा-शुल्क से पूर्णतया मुक्त रखा गया था। अब चूंकि देश में उत्पादन क्षमता आ गई है, इसलिए मैं घरेलू मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने के लिए ऐसे सेट टाप बाक्स पर 5 प्रतिशत का मामूली बुनियादी सीमा शुल्क लगाने का प्रस्ताव करता हूँ।

108. इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर उद्योग-विशेषतया लघु और अति लघु क्षेत्र में रोजगार सृजन की प्रबल संभावना है। मैं एलसीडी टेलीवीजन के स्वदेशी उत्पादन को सहायता प्रदान करने के लिए, एलसीडी पैनल पर बुनियादी सीमा शुल्क 10 प्रतिशत से घटा कर 5 प्रतिशत करना चाहता हूँ।

109. मोबाइल फोनों के विनिर्माण हेतु आयातित अतिरिक्त उपकरणों, कल पुर्जों और हिस्सों को 30 जून, 2009 तक 4 प्रतिशत के सेनैट शुल्क से पूर्ण छूट उपलब्ध थी। मैं एक और वर्ष के लिए यह छूट पुनः लागू रखने का प्रस्ताव करता हूँ।

110. कुछ स्पष्ट कारणों से निर्यातानुमुख उद्योग क्षेत्र ने वैश्विक बाजारों में मांग में कमी के चलते प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है। वर्तमान में कपड़ा, उत्पाद, वस्त्र परिधान, फुटवियर के साथ खेल के समान के निर्यातकों को उनके निर्यात के पोतपर्यन्त मूल्य के 3 प्रतिशत तक कच्चे माल, उपभोग्य वस्तुओं आदि के निःशुल्क आयात की अनुमति दी जाती है। मैं इन सूचियों में कुछ और मदों को जोड़ने का प्रस्ताव करता हूँ। मूल्य वर्द्धन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए खुरदरे मृगों को बुनियादी सीमा-शुल्क से पूर्ण छूट दी जा रही है।

111. यह अनिवार्य है कि यदि हमें ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के दृश्य का सफलतापूर्वक मुकाबला करना है तो विद्युत के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के लिए अंशदान बढ़ाना

होगा। मैं पवन चालित बिजली के जेनरेटरों हेतु महत्वपूर्ण संघटक स्थायी चुंबकों पर बुनियादी सीमा-शुल्क 7.5 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर रहा हूँ।

112. मैं इन्फ्लुएंजा टीकाकरण और स्तन कैंसर हेपेटाइटिस-बी, रुमेटिक आर्थराइटिस आदि के उपचार में प्रयोग होने वाली नौ विनिर्दिष्ट जीवन रक्षक दवाओं, और ऐसी दवाओं के विनिर्माण में प्रयोग होने वाली स्थूल दवाओं पर सीमा-शुल्क 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ। वे उत्पाद शुल्क अथवा प्रतिकारी शुल्क से भी पूर्णतया मुक्त होंगी।

113. हृदय सम्बन्धी उपचार में प्रयोग होने वाली दो विनिर्दिष्ट जीवन रक्षक मशीनों पर भी सीमा-शुल्क 7.5 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया जाएगा। ये मशीनें उत्पाद शुल्क और सेनवैट शुल्क से भी पूर्णतया मुक्त होंगी।

114. सोने की छड़ों पर, वर्तमान में 100 रुपये प्रति दस ग्राम की विशिष्ट दर से सीमा-शुल्क लगता है जबकि सोने के अन्य रूपों (आभूषणों को छोड़कर) पर 250 रुपये प्रति दस ग्राम का शुल्क प्रभावी है। ये दरें 2004 में नियत की गई थी और सोने के दाम कई गुणा बढ़ जाने के बावजूद भी, इनकी पुनरीक्षा नहीं की गई है। मैं ये दरें क्रमशः 200 रुपये प्रति दस ग्राम और 500 रुपये प्रति दस ग्राम बढ़ाकर इस प्रभाव को आंशिक रूप से बहाल करने का प्रस्ताव करता हूँ। इसी प्रकार, चांदी (आभूषण को छोड़कर) पर लगने वाला सीमा शुल्क बढ़ाकर 500 रुपये प्रति किलो ग्राम से 1000 रुपये प्रति किलो ग्राम किया जाएगा। वास्तविक यात्री द्वारा सामान के तौर पर आयात किए जाने वाले सोने तथा चांदी, जिसमें अजड़ित आभूषण शामिल हैं, पर भी ये संशोधित दरें लागू होंगी।

115. अब मैं केन्द्रीय उत्पाद शुल्कों की ओर आता हूँ।

116. माननीय सदस्य इस बात से अवगत हैं कि केन्द्र सरकार ने राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेजों की शृंखला की घोषणा की थी। इन पैकेजों की एक मुख्य विशेषता पेट्रोलियम-भिन्न उत्पादों के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की यथामूल्य दरों में 7 दिसम्बर, 2008 को सब पर लागू 4 प्रतिशत अंक तक काफी कमी करना और 24 फरवरी, 2009 को औसत सेनवैट दर में फिर से 2 प्रतिशत अंक की कमी करना था।

117. इन कटौतियों का एक परिणाम यह हुआ कि शुद्ध सूती कपड़ों को उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट दी गई। हमें ऐसे अभ्यावेदन मिले हैं कि पूरी छूट विनिर्माताओं को सेनवैट क्रेडिट से भुगतान किये जाने वाले निर्यात छूट लेने से वंचित करती है। मैं रेशे अवस्था के परे सूती कपड़ों के लिए पहले से प्रचलित 4 प्रतिशत की वैकल्पिक दर को बहाल करके इस स्थिति में सुधार लाने का प्रस्ताव करना चाहता हूँ।

118. जब से मेरे माननीय पूर्वाधिकारी द्वारा 2004 के बजट में कपड़ों के संबंध में उत्पाद शुल्क की संरचना का पुनरुद्धार किया गया है, कपास क्षेत्र और मानवनिर्मित क्षेत्र के बीच विभेदक दरें कायम रखी गई हैं। पहले के ढांचे के प्रति निष्ठा रखते हुए, मैं मानवनिर्मित

फाइबर और यार्न पर अनिवार्य रूप से 8 प्रतिशत उत्पाद शुल्क और फाइबर तथा यार्न की अवस्था के बाद वैकल्पिक आधार पर बहाल करने का प्रस्ताव रखता हूँ। इन परिवर्तनों का अभिप्राय यह है कि सभी प्रकार के मानवनिर्मित फाइबर तथा यार्न और उनके मध्यवर्तियों पर एक समान शुल्क लगेगा, जिससे ऋण संचयन की समस्या सुलझ जाएगी।

119. ऊन के अपशिष्ट और कपास के अपशिष्ट पर 15 प्रतिशत का सीमा-शुल्क प्रभावी होगा। इनका उपयोग सस्ते किस्म के कपड़े की वस्तुओं जैसे कम्बल और गलीचे के विनिर्माण करने के लिए किया जाता है। इस सैक्टर को राहत देने के उपाय के रूप में, मैं इन मदों पर बुनियादी सीमा-शुल्क में 10 प्रतिशत की कटौती करने का प्रस्ताव रखता हूँ।

120. राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर भाल तथा सेवा कर लगाने के उद्देश्य से सरकार की घोषणा से इस दिशा में कुछ और कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। एक उपाय जो इस प्रक्रिया को सुकर बना सकता है वह है केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की दरों को वर्तमान औसत दर अर्थात् 8 प्रतिशत के समाभिरूप बनाए रखना। मैंने वर्तमान में 4 प्रतिशत की दर वाली मदों की सूची की समीक्षा की है, यही दर औसत दर से कम है।

इस सूची में उल्लिखित कई मदों पर लगने वाली दर को 8 प्रतिशत तक बढ़ाने का मामला मेरे समक्ष है, जिसे मैं निम्नलिखित प्रमुख अपवादों सहित इस प्रकार करने का प्रस्ताव करता हूँ :

- खाद्य वस्तुएं; और
- औषध, भेषज तथा चिकित्सा उपस्कर।

कुछ मदें जिन पर मैं 4 प्रतिशत की दर बनाए रखने का प्रस्ताव करता हूँ, ये हैं :

- कागज, गत्ता तथा उनसे बनी वस्तुएं;
- जैसे प्रेशर कुकर सस्ते बिजली के बल्ब, सस्ते फुटवियर वाटर फिल्टर/प्यूरीफायर सीएफएल इत्यादि जैसी आम उपभोग की वस्तुएं;
- पानी के लिए बिजली चालित पम्प, और पेराक्सिलीन
- ब्यौरा संबंधित अधिसूचनाओं में उपलब्ध है।

121. वनस्पति तेलों से प्राप्त और पेट्रो-डीजल के समिश्रण में प्रयुक्त किए जाने वाले बायोडीजल पर इस समय उत्पाद शुल्क से छूट है। मैं अब बायोडीजल के साथ सम्मिश्रित पेट्रो-डीजल को उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट देने का प्रस्ताव करता हूँ।

122. देश में इस पर्यावरण अनुकूल ईंधन के प्रयोग को बढ़ावा देने तथा उसकी उपलब्धता बढ़ाने के लिए मैं पेट्रो-डीजल की तरह ही बायो डीजल पर बुनियादी सीमा-शुल्क 7.5 प्रतिशत से घटाकर 2.5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ। मुझे आशा है कि इन प्रस्तावों से ग्रीन बिग्रेड के चेहरों पर मुस्कान खिलेगी!

123. केन्द्रीय उत्पाद शुल्कों संबंधी मेरे प्रस्तावों में उन गड़बड़ियों का समाधान ढूँढने का प्रयास किया गया है, जिनके बारे में विनिर्माण उद्योग शिकायत करता रहा है।

124. सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग ने इस ओर ध्यान दिलाया है कि वह उस साफ्टवेयर के निर्धारण में कठिनाइयों का सामना कर रहा है, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी साफ्टवेयर सेवा पर सेवा कर लगने के बाद प्रयोग हेतु अधिकार का अंतरण शामिल है। इस मामले को सुलझाने के लिए मैं संवेष्टित साफ्टवेयर के प्रयोग के लिए अधिकार के अंतरण में लगने वाले मूल्य को उत्पाद शुल्क तथा सीवीडी से छूट देने का प्रस्ताव करता हूँ।

125. निर्माण उद्योग ने निवेदन किया है कि वह कार्यस्थल पर विनिर्मित वस्तुओं पर मिलने वाली छूट हटाने के कारण कठिनाइयों का सामना कर रहा है। मैं ऐसी वस्तुओं जिनमें कार्यस्थल पर अगला निर्माण कार्य करने में प्रयुक्त होने वाले निर्मित पूर्व कांक्रिट स्लैब अथवा खण्ड शामिल हैं, पर मिलने वाली पूरी छूट बहाल करने का प्रस्ताव करता हूँ।

126. पिछले वर्ष जून में बड़ी कारों तथा जनोपयोगी वाहनों पर प्रयोज्य 24 प्रतिशत के यथामूल्य शुल्क में एक विशिष्ट घटक जोड़ा गया था। 2000 सीसी से कम की क्षमता के इंजन वाले वाहनों के मामले में यह घटक यूनिट 15,000 रुपए था जबकि उच्च क्षमता के इंजन वाले वाहनों के लिए यह प्रति यूनिट 20,000 रुपया था। इन दरों को अब एकीकृत करके 15,000 रुपए प्रति यूनिट के निम्न स्तर पर किया जा रहा है।

127. पेट्रोल से चलने वाले ट्रक शहरों तथा कम दूरियों के लिए परिवहन का एक उपयोगी साधन है। इन पर 20 प्रतिशत उत्पाद शुल्क लगाया जाता है। मैं इन ट्रकों पर लगने वाले उत्पाद शुल्क को घटाकर 8 प्रतिशत करने ताकि इसे डीजल से चलने वाले इसी तरह के वाहनों के उत्पाद शुल्क के बराबर किया जा सके प्रस्ताव करता हूँ।

128. अध्यक्ष महोदया, मुझे आशांका है कि सोने और चांदी पर सीमा शुल्क लगाने संबंधी मेरे प्रस्ताव से महिलाओं के मध्य मेरी लोकप्रियता कुछ हद तक कम होगी। मैं ब्रांडेड आभूषणों को उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट देकर इससे उबरने का प्रस्ताव करता हूँ।

129. अब मैं सेवा कर संबंधी अपने प्रस्तावों की ओर बढ़ता हूँ।

130. शून्य दर निर्यात एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी है। इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए, 2007 में एक योजना घोषित की गई थी जिसमें कारखाने से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के समाशोधन के पश्चात् प्रयुक्त की गई कतिपय कर योग्य सेवाओं पर अदा किए गए सेवा कर की वापसी की मंजूरी दी गई थी। कुछ समय से निर्यातक समुदाय ऐसी वापसियां प्राप्त करने में आने वाली कठिनाइयों पर असंतोष व्यक्त करता रहा है। विगत मैं प्रक्रियागत सरलीकरण के लिए किए गए कई प्रयासों से भी संतोषजनक परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं। लगता है इसका हल निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत किए गए दावों पर अधिक भरोसा करने में ही है। इसे देखते हुए, मैं इस योजना में निम्नलिखित परिवर्तन करने का प्रस्ताव करता हूँ :

- निर्यातकों द्वारा गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंटों तथा कमिशन एजेंटों से प्राप्त की गई सेवाओं, जहां सेवा कर अदा करने का दायित्व प्रारंभ से ही निर्यातकों पर है पर सेवा कर की छूट

होगी। इस प्रकार निर्यातकों को पहले कर अदा करने और बाद में वापसी का दावा करने की कोई जरूरत नहीं होगी।

- निर्यातकों को प्राप्त होने वाली अन्य सेवाओं के लिए मौजूदा धन वापसी तंत्र के जरिए छूट प्रदान की जाएगी। यह पोत पर्यन्त (एफओबी) मूल्य के 0.25 प्रतिशत से कम की वापसी दस्तावेजों के स्व-प्रमाणन पर और इस सीमा से अधिक की वापसी मूल्य के लिए सनदी लेखाकार द्वारा दस्तावेजों के प्रमाणन पर आधारित होगी।

131. निर्यात संवर्धन परिषद् और भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ (एफआईईओ) हमारे निर्यात प्रयास के संवर्धन में बहुमूल्य सेवा प्रदान करते हैं। मैं उनकी सदस्यता पर सेवा कर के उद्ग्रहण और उनके द्वारा संग्रहित अन्य शुल्कों को 31 मार्च, 2010 तक छूट देने का प्रस्ताव करता हूँ।

132. माल परिवहन क्षेत्र में सेवा कर वर्तमान में सड़क मार्ग, वायु मार्ग द्वारा, पाइपलाइनों के जरिए और कंटेनरों में माल के परिवहन पर लगाया जाता है। तथापि भारतीय रेल द्वारा अथवा तटीय कार्गो के रूप में अथवा अंतरदेशीय जल मार्गों के जरिए ढोए जाने वाले माल पर सेवा कर नहीं लिया जाता है। माल परिवहन क्षेत्र में समान स्तर का दृष्टिकोण रखते हुए, मैं माल परिवहन के इन तरीकों पर सेवा कर लगाए जाने का प्रस्ताव करता हूँ। इस नए कर उद्ग्रहण से अनिवार्य वस्तुओं अथवा आम जनता के उपभोग की वस्तुओं के मूल्यों पर प्रभाव पड़ने की संभवना नहीं है, क्योंकि इस संबंध में उपयुक्त छूट प्रदान की जाएगी।

133. जैसा कि माननीय सदस्यों को पता है, वर्तमान सनदी लेखाकारों, लागत लेखाकारों और कंपनी सचिवों के साथ-साथ इंजीनियरिंग और प्रबंधन परामर्शदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर सेवा कर लगाया जाता है। यद्यपि ऐसी सोच है कि विधिक परामर्शदाता अपने मुक्किल को कोई सेवा प्रदान नहीं करते हैं, परन्तु अपने माननीय पूर्ववर्ती का सम्मान करते हुए मेरी उनसे अलग राय है। इस प्रकार मैं विधि के क्षेत्र में प्रदान की जाने वाली सलाह परामर्श अथवा तकनीकी सहायता पर सेवा कर लगाने का प्रस्ताव करता हूँ। परन्तु सेवा प्रदाता अथवा सेवा प्राप्त करने वाले के व्यक्ति होने की स्थिति में यह कर लागू नहीं होगा।

134. 'स्टेज कैरिज परमिट' वाले और राज्य उपक्रमों द्वारा चलाए जाने वाले वाहनों को सेवा कर से छूट प्राप्त है। तथापि निजी, उद्यमों द्वारा संचालित 'कॉन्ट्रेक्ट कैरिज परमिट' वाले वाहनों में यात्रियों को परिवहन सेवा, सेवा कर के अधीन होती है। कर व्यवहार में समानता लाने के लिए मैं ऐसे परिवहन को सेवा कर से छूट प्रदान करता हूँ।

135. जुलाई, 2008 में माल परिवहन एजेंट (जीटीए) अनेक मांग करते हुए हड़ताल पर चले गए थे। माल परिवहन एजेंटों को मार्ग में प्रदान की जाने वाली पैकिंग कार्गो की धराई-उतराई, भांडागारण जैसी कतिपय सेवाओं के संबंध में छूट की मांग को सरकार ने स्वीकार कर लिया था। इस प्रयोजन के लिए छूट संबंधी

अधिसूचना जारी की गई थी। माल परिवहन एजेंटों द्वारा यह भी मांग की गई थी कि ऐसे सेवा प्रदाताओं के विरुद्ध पहले से शुरू की गई कार्रवाइयों को छोड़ दिया जाए। सरकार ने इस उचित मांग को स्वीकार कर लिया है। अतः मैं इस वायदे को पूरा करने के लिए अपेक्षित कतिपय विधायी परिवर्तन करने का प्रस्ताव करता हूँ।

136. सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर में परिवर्तन करने संबंधी अधिसूचनाओं की प्रतियां सदन के पटल पर यथा समय रख दी जाएंगी।

137. प्रत्यक्ष करों पर मेरे कर प्रस्तावों से राजस्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अप्रत्यक्ष करों पर पूरे वर्ष के लिए 2000 करोड़ रुपए का निवल लाभ प्राप्त होने का अनुमान है।

निष्कर्ष

138. चूंकि हम अपनी पांच वर्षीय यात्रा शुरू कर रहे हैं, आगे का मार्ग आसान नहीं होगा। हमें अनिश्चितताओं का सामना करना होगा और जितनी समस्याएं होंगी, उतना ही उनका समाधान होगा। मैं महात्मा गांधी के कथन को उद्धृत करना चाहूंगा, 'लोकतंत्र लोगों के विभिन्न वर्गों के समग्र भौतिक, आर्थिक और आध्यात्मिक संसाधनों को जुटाने की कला और विज्ञान है जिसमें सभी की सामान्य भलाई अंतर्निहित है।' यह स्पष्ट रूप से वही कार्य है जो हमें पूरा करना है। पूरे दिल से, पूरी बुद्धिमत्ता से और पूरी इच्छा शक्ति से हमें अपने सपनों के भारत का निर्माण करने के लिए सभी विपरीत परिस्थितियों का मुकाबला करना और सभी अवरोधों को दूर करना है।

139. अध्यक्ष महोदया, इन शब्दों के साथ मैं यह बजट सदन को समर्पित करता हूँ।"

शक्तिकान्ता दास, संयुक्त सचिव (बजट)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(BUDGET DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th July, 2009

No. F 2(36)-B(D)/2009.—The following is published for general information :—

"Budget 2009-2010

Speech of Shri Pranab Mukherjee, Minister of Finance

July 6, 2009

Madam Speaker,

I rise to present the Budget for 2009-10.

2. Just 140 days back, I had the privilege to present the Interim Budget for 2009-10. It is a rare honour that I have been called upon to present the regular budget after the new Government assumed office.

3. The Congress-led UPA Government has come back to power with a renewed mandate. As Prime Minister, Dr. Manmohan Singh, said recently "It is a mandate for

continuity, stability and prosperity. It is a mandate for inclusive growth and equitable development." It is a mandate that we accept with humility and a firm resolve to do all that we can for the welfare of this Nation.

4. I am deeply conscious of the faith reposed by the people in our Government and the responsibilities that come with it. I am sensitive to the great challenge of rising expectations of a young India. It reflects a population that is restless, yet engaged and is ready to seize the opportunities that it is presented with. There are new and powerful reasons for us to create, facilitate and sustain those opportunities.

5. In the Interim Budget for 2009-10, I had stated that the new Government would need to anchor its policies for 2009-10, in a medium term perspective that would have to :

- (a) sustain a growth rate of at least 9 per cent per annum over an extended period of time;
- (b) strengthen the mechanisms for inclusive growth for creating about 12 million new work opportunities per year;
- (c) reduce the proportion of people living below poverty line to less than half from current levels by 2014;
- (d) ensure that Indian agriculture continues to grow at an annual rate of 4 per cent;
- (e) increase the investment in infrastructure to more than 9 per cent of GDP by 2014;
- (f) support Indian industry to meet the challenge of global competition and sustain the growth momentum in exports;
- (g) strengthen and improve the economic regulatory framework in the country;
- (h) expand the range and reach of social safety nets by providing direct assistance to vulnerable sections;
- (i) strengthen the delivery mechanism for primary health care facilities with a view to improve the preventive and curative health care in the country;
- (j) create a competitive, progressive and well regulated education system of global standards that meets the aspiration of all segments of the society; and
- (k) move towards providing energy security by pursuing an Integrated Energy Policy.

6. The Government recognizes the challenges that this task entails, particularly at a time when the world is still struggling with an unprecedented financial crisis and an economic slowdown that has also affected India. While we are determined to convert our words into deeds, Members would appreciate that a single Budget Speech cannot solve all our problems, nor is the Union Budget the only instrument to do so. Yet, it is an important means to share the vision of the Government, particularly as we begin a new term. I propose to do just that for the next hour or so,

as I dwell on the challenges and outline the approach of the Government in the short term and medium term perspectives.

7. The *first challenge* is to lead the economy back to the high GDP growth rate of 9 per cent per annum at the earliest. Growth of income is important in itself, but it is as important for the resources that it brings in. These resources provide us with the means to bridge the critical gaps that remain in our development efforts, particularly with regard to the welfare of the vulnerable segments of our population.

8. The *second challenge* is to deepen and broaden the agenda for inclusive development; and to ensure that no individual, community or region is denied the opportunity to participate in and benefit from the development process.

9. The *third challenge* is to re-energize Government and improve delivery mechanisms. Our institutions must provide high quality public services, security and the rule of law to all citizens with transparency and accountability.

Overview of the Economy

10. Madam Speaker, at the time of the presentation of the Interim Budget, I had given a detailed analysis of the economic situation. Without repeating myself, I would like to highlight that the development course charted by the UPA Government in the last five years has been possible due to a step up in the growth rate of the economy and improved revenue buoyancy. The principal growth driver in this period has been private investment, which has been predominantly funded by domestic resources. During the year 2008-09, there has been a dip in the growth rate of GDP from an average of over 9 per cent in the previous three fiscal years to 6.7 per cent. It has affected the pace of job creation in certain sectors of the economy and the investment sentiments of the business community. It has also resulted in considerably lower revenue growth for the government. Another feature of the year 2008-09 was a sharp rise in the wholesale price index to nearly 13% in August, 2008 and an equally sharp fall close to 0% in March 2009. While a detailed analysis of the developments has been presented in the Economic Survey-2008-09, tabled in both houses of Parliament last Thursday, I draw your attention to a few aspects.

11. The structure of India's economy has changed rapidly in the last ten years. External trade and external capital flows are an important part of the economy and so is the contribution of the services sector to the GDP at well over 50 per cent. The share of merchandise trade (exports plus imports) as a proportion of GDP has more than doubled over the past decade to 38.9 per cent in 2008-09. Similarly, trade in goods and services taken together has also doubled to 47 per cent during this period. Gross capital flows rose to a peak of over 9 per cent of GDP in 2007-08 before falling in the wake of the global financial crisis. The significant increase in the inflow of foreign capital is important, not so much for bridging the domestic savings-investment gap, but for facilitating the intermediation of financial resources to meet the growing needs of the economy.

12. This growing integration of the Indian economy with the rest of the world has brought new opportunities and also new challenges. It has made the task of sustaining high growth more complex. Over the past month, we have critically evaluated Government's efforts at both short term economic recovery as well as medium term economic growth. The economic recovery and growth is a cooperative effort of the Central and State Governments. That is why, for the first time, I held a meeting with Finance Ministers of States as part of the preparations for this Budget. I intend to make this an annual feature.

TOWARDS ECONOMIC REVIVAL

Short-term measures

13. To counter the negative fallout of the global slowdown on the Indian economy, the Government responded by providing three focused fiscal stimulus packages in the form of tax relief to boost demand and increased expenditure on public projects to create employment and public assets. The RBI took a number of monetary easing and liquidity enhancing measures to facilitate flow of funds from the financial system to meet the needs of productive sectors.

14. This fiscal accommodation led to an increase in fiscal deficit from 2.7 per cent in 2007-08 to 6.2 per cent of GDP in 2008-09. The difference between the actuals of 2007-08 and 2008-09 constituted the total fiscal stimulus. This fiscal stimulus at 3.5% of GDP at current market prices for 2008-09 amounts to Rs. 1,86,000 crore.

15. These measures were effective in arresting the fall in growth rate of GDP in 2008-09 and we achieved a growth of 6.7 per cent. There are signs of revival in the domestic industry and the foreign investors have also returned to the Indian market in the last couple of months. It is possible that the two worst quarters since the global financial meltdown in September, 2008 are behind us. While the global financial conditions have shown improvement over the recent months, uncertainties relating to the revival of the global economy remain. We cannot, therefore, afford to drop our guard. We have to continue our efforts to provide further stimulus to the economy.

16. Madam Speaker, what I unfold now are only the 'First steps'. It will be my endeavour to make the process of budget formulation more participatory and a continuous exercise.

Infrastructure Development

17. To stimulate public investment in infrastructure, we had set up the India Infrastructure Finance Company Limited (IIFCL) as a special purpose vehicle for providing long term financial assistance to infrastructure projects. We will ensure that IIFCL is given greater flexibility to aggressively fulfil its mandate.

18. 'Takeout financing' is an accepted international practice of releasing long term funds for financing infrastructure projects. It can be used to effectively address the asset liability mismatch of commercial banks arising out of financing infrastructure projects and also to free up

capital for financing new projects. IIFCL would, in consultation with banks, evolve a 'takeout financing' scheme which could facilitate incremental lending to the infrastructure sector.

19. Government has had some success in attracting private investment in a wide range of infrastructure sectors such as telecommunications, power generation, airports, ports, roads and even in railways through public private partnerships (PPP). To ensure that infrastructure projects do not face financing difficulties arising from the current downturn, as I indicated in my Interim Budget Speech, the Government has decided that IIFCL will refinance 60 per cent of commercial bank loans for PPP projects in critical sectors over the next fifteen to eighteen months. The IIFCL and Banks are now in a position to support projects involving a total investment of Rs. 100 thousand crore in infrastructure. Combined with the steps we are taking to increase public investment in infrastructure, this will provide a big boost to such investment.

20. The investment in infrastructure for the growth of economy is critical. I have urged my colleagues in the Central and State Governments to remove policy, regulatory and institutional bottlenecks for speedy implementation of infrastructure projects. I, on my part, will ensure that sufficient funds are made available for this sector.

Highway and Railways

21. The allocation during the current year to National Highways Authority of India (NHAI) for the National Highways Development Programme (NHDP) is being stepped up by 23 per cent over the 2008-09 (BE). I have also increased the allocation for the Railways from Rs. 10,800 crore made in the Interim Budget for 2009-10 to Rs. 15,800 crore.

Urban Infrastructure

22. The Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission (JNNURM) has been an important instrument for refocusing the attention of the State Governments on the importance of urban infrastructure. In recognition of the role of JNNURM, the allocation for this scheme is being stepped up by 87 per cent to Rs. 12,887 crore in the current budget. To improve the lot of the urban poor, I propose to enhance the allocation for housing and provision of basic amenities to urban poor to Rs. 3,973 crore in the current year's budget. This includes the provision for Rajiv Awas Yojana (RAY), a new scheme announced in the address of the President of India. This scheme, the parameters of which are being worked out, is intended to make the country slum free in the five year period.

Brihan Mumbai Storm Water Drainage Project (BRIMSTOWA)

23. To address the problem of flooding in Mumbai, Brihan Mumbai Storm Water Drainage Project (BRIMSTOWA) was initiated in 2007. The entire estimated cost of the project at Rs. 1,200 crore is being funded through Central assistance. A sum of Rs. 500 crore has been released for this project upto 2008-09. I have enhanced the provision for this project from Rs. 200 crore in Interim BE to Rs. 500 crore to expedite the completion of the project.

Power

24. The Accelerated Power Development and Reform Programme (APDRP) is an important scheme for reducing the gap between power demand and supply. I propose to increase the allocation for this scheme to Rs. 2,080 crore, a steep increase of 160 per cent above the allocation in the BE of 2008-09.

Gas

25. With the recent find of natural gas in the KG Basin on the Eastern offshore of the country, the indigenous production of Natural Gas is set to double with natural gas emerging as an important source of energy. LNG infrastructure in the country is also being expanded. Government proposes to develop a blueprint for long distance gas highways leading to a National Gas Grid. This would facilitate transportation of gas across the length and breadth of the country.

Assam Gas Cracker Project

26. The Assam Gas Cracker Project sanctioned in April 2006 is being executed at a cost of Rs. 5,461 crore. The capital subsidy of Rs. 2,138 crore for the project is to be provided by the Central Government. The outlay for this project is being stepped up suitably.

Agricultural Development

I now turn to Agricultural development.

27. Agriculture has been the mainstay of our economy with 60 per cent of our population deriving their sustenance from it. In the recent past, the sector has recorded a growth of about 4 per cent per annum with substantial increase in plan allocations and capital formation in the sector. Agriculture credit flow was Rs. 2,87,000 crore in 2008-09. The target for agriculture credit flow for the year 2009-10 is being set at Rs. 3,25,000 crore. To achieve this, I propose to continue the interest subvention scheme for short term crop loans to farmers for loans upto Rs. 3 lakh per farmer at the interest rate of 7 per cent per annum. I am also happy to announce that, for this year, the Government shall pay an additional subvention of 1 per cent as an incentive to those farmers who repay their short term crop loans on schedule. Thus, the interest rate for these farmers will come down to 6 per cent per annum. For this, I am making an additional Budget provision of Rs. 411 crore over Interim BE.

Debt Relief for farmers

28. The one-time bank loan waiver of nearly Rs. 71,000 crore to cover an estimated 40 million farmers was one of the major highlights of the last Budget. Under the Agricultural Debt Waiver and Debt Relief Scheme (2008), farmers having more than two hectares of land were given time upto 30th June, 2009 to pay 75% of their overdue. Due to the late arrival of monsoon, I propose to extend this period by six months upto 31st December, 2009.

29. It is learnt that in some regions of Maharashtra, a large number of farmers had taken loans from private money lenders and the loan waiver scheme did not cover them. The matter requires special attention. To examine the

matter in greater detail and suggest the future course of action, I propose to set up a Taskforce.

Accelerated Irrigation Benefit Programme

30. I propose to provide an additional Rs. 1,000 crore over Interim BE for the Accelerated Irrigation Benefit Programme (AIBP), marking an increase of 75 per cent over the allocation in 2008-09(BE). The allocation for the Rashtriya Krishi Vikas Yojna (RKVY) is also being stepped up by 30 per cent over Budget Estimates of 2008-09.

Restoring Export Growth

31. Our exporters by virtue of their close links to the external sector have borne the brunt of the global economic crisis. It is, therefore, appropriate that we continue to provide all possible assistance to our exporters to help them overcome the short term disadvantages. More specifically :

- (a) An adjustment assistance scheme to provide enhanced Export Credit and Guarantee Corporation (ECGC) cover at 95 per cent to badly hit sectors had been initiated in December 2008 to mitigate the difficulties faced by the exporters. In view of the continuing contraction in exports, I propose to extend the benefits of this scheme up to March 2010.
- (b) The Market Development Assistance Scheme provides support to exporters in developing new markets. With many traditional markets still under financial stress, greater effort is required to identify and develop new markets. I propose to enhance the allocation for this scheme by 148% over BE 2008-09 to Rs. 124 crore.
- (c) With a view to insulating the employment-oriented export sectors from the global meltdown, Government had provided an interest subvention of 2 per cent on pre-shipment credit for seven such sectors. These sectors are textiles including handlooms, handicrafts, carpets, leather, gems and jewellery, marine products and small and medium exporters. I propose to extend the interest subvention beyond the current deadline of September 30, 2009 to March 31, 2010.
- (d) Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) have been affected by the slowdown in exports and the indirect effect of the global crisis on domestic demand. To support this sector, I propose to facilitate the flow of credit at reasonable rates, by providing a special fund out of Rural Infrastructure Development Fund (RIDF) to Small Industries Development Bank (SIDBI). This fund of Rs. 4,000 crore will incentivise Banks and State Finance Corporations (SFCs) to lend to Micro and Small Enterprises (MSEs) by refinancing 50 per cent of incremental lending to MSEs during the current financial year.

- (e) In February, 2009 the Print Media was given a stimulus package comprising waiver of 15% agency commission on DAVP advertisements and a 10% increase in the DAV Prates to be paid as a 'special relief' subject to documentary proof of loss of revenue in non-governmental advertisements. Since Print Media is still passing through difficult times, I have decided to extend the stimulus package for another six months from 30th June, 2009 to 31st December, 2009.

Medium-term sustainability

32. The short term fiscal stimulus has to be balanced against long term prudence and fiscal sustainability objectives. To quote Kautilya, "In the interest of the prosperity of the country, a King shall be diligent in foreseeing the possibility of calamities, try to avert them before they arise, overcome those which happen, remove all obstructions to economic activity and prevent loss of revenue to the state". I intend to take Kautilya's advice and return to the FRBM target for fiscal deficit at the earliest and as soon as the negative effects of the global crisis on the Indian economy have been overcome. On the medium term fiscal perspective, I await the recommendations of the 13th Finance Commission.

33. To bring the fiscal deficit under control, we have to initiate institutional reform measures during the current year itself. This is essential for maintaining a stable balance of payments, moderate interest rates and steady flow of external capital for corporate investment. These measures have to encompass all aspects of the budget such as subsidies, taxes, expenditure and disinvestment.

Fertilizer subsidy

34. In the context of the nation's food security, the declining response of agricultural productivity to increased fertilizer usage in the country is a matter of concern. To ensure balanced application of fertilizers, the Government intends to move towards a nutrient based subsidy regime instead of the current product pricing regime. It will lead to availability of innovative fertilizer products in the market at reasonable prices. This unshackling of the fertilizer manufacturing sector is expected to attract fresh investments in this sector. In due course it is also intended to move to a system of direct transfer of subsidy to the farmers.

Petroleum and Diesel pricing policy

35. Madam Speaker, Honourable Members are aware that global prices of oil and petroleum products had shot up to unprecedented levels in 2008-09. Most oil importing countries, including our neighbours, adjusted their domestic prices to reflect these global changes. Though prices have declined since then, they are already about double of the lows reached in the wake of the global financial crisis. It is important to recognise that, with almost three-quarters of our oil

consumption met through imports, domestic prices of petrol and diesel have to be broadly in sync with global prices of these items. Government will set up an expert group to advise on a viable and sustainable system of pricing petroleum products. Details will be announced by my colleague, the Minister of Petroleum and Natural Gas.

Taxation

36. It is time that we complete the process that was started in 1991 for building a trust based, simple, neutral, tax system with almost no exemptions and low rates designed to promote voluntary compliance. The Income Tax Return Forms should be simple and user-friendly. I have asked the Department to work on SARAL-II forms for early introduction. We need a tax system which generates revenues on a sustained basis without use of coercive tax collection methods at the end of each year to meet targets. It is my intention to make a modest start in this direction in the current year and ensure that the process is completed in the next four years. At the end of this process, I hope the Finance Minister can credibly say that our tax collectors are like honey bees collecting nectar from the flowers without disturbing them, but spreading their pollen so that all flowers can thrive and bear fruit.

People's ownership of PSUs

37. The Public Sector Undertakings are the wealth of the nation, and part of this wealth should rest in the hands of the people. While retaining at least 51 per cent Government equity in our enterprises, I propose to encourage people's participation in our disinvestment programme. Here, I must state clearly that public sector enterprises such as banks and insurance companies will remain in the public sector and will be given all support, including capital infusion, to grow and remain competitive.

Financial sector

38. The financial sector is the life blood of any economy. Our Government's approach to the banking and financial sector has been to ensure robust oversight and regulation while expanding financial access and deepening markets. The merit of this balanced approach has been borne out in the recent experience, as the turbulence in the world financial markets has left the Indian banking and financial sector relatively unaffected. Never before has Indira Gandhi's bold decision to nationalise our banking system exactly 40 years ago—on 14th of July, 1969—appeared as wise and visionary as it has over the past few months. Her approach continues to be our inspiration even as we introduce competition and new technology in this sector.

39. The average public float in Indian listed companies is less than 15 per cent. Deep non-manipulable markets require larger and diversified public shareholdings. This requirement should be uniformly applied to the private sector as well as listed public sector companies. I propose to raise, in a phased

manner, the threshold for non-promoter public shareholding for all listed companies.

40. For a country like ours, with significant sections of unbanked population and regions, financial inclusion is vital for sustaining long term equitable development. As part of the financial inclusion drive, scheduled commercial banks have been opening 'no frills' accounts either with 'nil' or very low minimum balances. So far, these banks have opened 3.3 crore such accounts. The RBI has announced a further relaxation in its Branch Authorisation Policy. Scheduled Commercial Banks are now allowed to set up off-site ATMs without prior approval, subject to reporting.

41. Despite the expansion of banking network in the country, there are still some areas that remain underbanked or unbanked. A sub-committee of State Level Bankers Committee (SLBC) will identify such areas and formulate an action plan for providing banking facilities to all these areas in the next 3 years. I propose to set aside Rs. 100 crore during the current year as one-time grant-in-aid to ensure provision of at least one Centre/Point of Sales (POS) for banking services in each of the unbanked blocks in the country.

42. The Government has established Competition Commission of India, an autonomous regulatory body to promote and sustain competition in markets, protect interests of consumers and to prevent practices having adverse effect on competition. An Appellate body headed by a retired judge of the Supreme Court has also been constituted.

43. The benefits of competition should now come to more sectors and their users and consumers. Now is the time for us to work on these aspects to eliminate supply bottlenecks, enhance productivity, reduce costs and improve quality of goods and services supplied to consumers.

Investment environment

44. Private sector investment has been affected by the global macro economic conditions. Our Government is committed to creating a facilitating environment in which a competitive private sector can thrive and play its rightful role in nation's economic development. India's high growth of 8.5% per annum from 2004 to 2008 was fuelled in very large part by private investment. I look forward to working closely with industry and our vibrant entrepreneurial community to address their outstanding concerns.

TOWARDS INCLUSIVE DEVELOPMENT

45. Madam Speaker, the UPA government has gone for a paradigm shift for making the development process more inclusive. It involves creating entitlements backed by legal guarantee to provide basic amenities and opportunities for livelihood to vulnerable sections. 'Aam Admi' is now the focus of all our programmes and schemes.

National Rural Employment Guarantee Scheme (NREGS)

46. (i) It is widely acknowledged that the National Rural Employment Guarantee Act (NREGA), first implemented in February 2006, has been a magnificent success. During 2008-09, NREGA provided employment opportunities for more than 4.47 crore households as against 3.39 crore households covered in 2007-08. We are committed to providing a real wage of Rs. 100 a day as an entitlement under the NREGA. To increase the productivity of assets and resources under NREGA, convergence with other schemes relating to agriculture, forests, water resources, land resources and rural roads is being initiated. In the first stage, a total of 115 pilot districts have been selected for such convergence. Details of these measures and convergence guidelines will be announced by my colleague, the Minister of Rural Development. I propose an allocation of Rs. 39,100 crore for the year 2009-10 for NREGA which marks an increase of 144% over 2008-09 Budget Estimates.

National Food Security Act (NFSA)

(ii) I am happy to announce that the work on National Food Security Act has begun in right earnest. This will ensure that every family living below the poverty line in rural or urban areas will be entitled by law to 25 kilos of rice or wheat per month at Rs. 3 a kilo. The Government proposes to put the draft Food Security Bill on the website of the Department of Food and Public Distribution for public debate and consultations very soon.

Bharat Nirman

(iii) Bharat Nirman with its six schemes is an important initiative for bridging the gap between the rural and urban areas and improving the quality of life of people, particularly the poor, in the rural areas. I propose to step up the allocations for Bharat Nirman by 45 per cent in 2009-10 over the BE of 2008-09. The Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY) is one of the most successful programmes under Bharat Nirman. I propose to step up the allocation for this programme by 59% over BE 2008-09 to Rs.12,000 crore. I also propose to allocate Rs.7,000 crore to Rajiv Gandhi Grameen Viduytikaran Yojana (RGGVY) which represents a 27 per cent increase over 2008-09 (BE).

(iv) The allocation for the Indira Awaas Yojana (IAY) is proposed to be increased by 63 per cent to Rs. 8,800 crore in Budget Estimates 2009-10. To broaden the pace of rural housing, I propose to allocate, from the shortfall in the priority sector lending of commercial banks, a sum of Rs. 2,000 crore for Rural Housing Fund in the National Housing Bank (NHB). This will boost the resource base of NHB for their refinance operations in rural housing sector.

Pradhan Mantri Adarsh Gram Yojana (PMAGY)

(v) There are about 44,000 villages in which the population of Scheduled Castes is above 50 per cent. A

new scheme called Pradhan Mantri Adarsh Gram Yojana (PMAGY) is being launched this year on a pilot basis, for the integrated development of 1000 such villages. I propose an allocation of Rs. 100 crore for this scheme. Each village would be able to avail gap funding of Rs. 10 lakh over and above the allocations under Rural Development and Poverty Alleviation Schemes. On successful implementation of the pilot phase, the Yojana would be extended in coming years.

Empowerment of Weaker Sections

47. The Swarna Jayanti Gram Swarozgar Yojna (SGSY) is being restructured as the National Rural Livelihood Mission to make it universal in application, focused in approach and time bound for poverty eradication by 2014-15. Stress will be laid on the formation of women Self Help Groups (SHGs). Apart from providing capital subsidy at an enhanced rate, it is also proposed to provide interest subsidy to poor households for loans upto Rs. one lakh from banks.

48. The Women's Self Help Group movement is bringing about a profound transformation in rural areas. There are today over 22 lakh such groups linked with banks. Our objective is to enrol at least 50% of all rural women in India as members of SHGs over the next five years and link these SHGs to banks.

49. The Rashtriya Mahila Kosh has been working towards the facilitation of credit support or micro finance to poor women and has developed a number of innovative schemes for their benefit. In recognition of its role as an instrument of socio-economic change and development, the corpus of the Kosh, which at present is Rs. 100 crore, would be raised to Rs. 500 crore, over the next few years.

Female literacy

50. The low level of female literacy continues to be a matter of grave concern. It has, therefore, been decided to launch a National Mission for Female Literacy, with focus on minorities, SC, ST and other marginalised groups. The aim will be to reduce by half, the current level of female illiteracy, in three years.

Integrated Child Development Services

51. Government is committed to universalisation of the Integrated Child Development Services (ICDS) Scheme in the country. By March 2012, all services under ICDS would be extended, with quality, to every child under the age of six.

Student Loans to Weaker Sections

52. To enable students from economically weaker sections to access higher education, it is proposed to introduce a scheme to provide them full interest subsidy during the period of moratorium. It will cover loans taken by such students from scheduled banks to pursue any of the approved courses of study, in technical and professional streams, from recognised institutions in India. It is estimated that over 5 lakh students would avail of this benefit.

Welfare of Minorities

53. The Plan outlay of Ministry of Minority Affairs has been enhanced from Rs.1,000 crore in BE 2008-09 to Rs. 1,740 crore in 2009-10, registering an increase of 74%. This includes Rs. 990 crore for Multi-Sectoral Development Programme for Minorities in selected minority concentration districts, Grants-in-aid to Maulana Azad Education Foundation which is almost doubled, and provisions for National Minorities Development and Finance Corporation and Pre-Matric and Post-Matric Scholarships for Minorities. Allocations have also been made for the new schemes of National Fellowship for Students from the Minority Community and Grants-in-aid to Central Wakf Council for computerization of records of State Wakf Boards.

54. Aligarh Muslim University has decided to establish its campuses at Murshidabad in West Bengal and Malappuram in Kerala. I propose to make an allocation of Rs. 25 crore each for these two campuses.

Welfare of workers in the unorganised sector

55. The unorganised or informal sector of our economy accounts for 92% of the employment and absorbs bulk of the annual increase in our labour force. The Unorganised Workers Social Security Bill, 2007 has now been passed by both Houses of Parliament. I have already initiated action to ensure that social security schemes for occupations like weavers, fishermen and women, toddy tappers, leather and handicraft workers, plantation labour, construction labour, mine workers, bidi workers, and rikshaw pullers are implemented at the earliest. Necessary financial allocations will be made for these schemes.

Employment Exchanges

56. I propose to launch a new project for modernisation of the Employment Exchanges in public private partnership so that a job seeker can register on-line from anywhere and approach any employment exchange. Under the project, a national web portal with common software will be developed. This will contain all the data regarding availability of skilled persons on the one hand and requirements of skilled persons by the industry on the other. It will help youth get placed and enable industry to procure required skills on real time basis.

Handlooms

57. In the last Budget two mega handloom clusters at Varanasi and Sibsagar and two mega powerloom clusters at Erode and Bhiwandi were approved. They are under successful implementation. I propose to add one handloom mega cluster each in West Bengal and Tamil Nadu and one powerloom mega cluster in Rajasthan. These will help preserve the magnificent textile traditions in West Bengal and Tamil Nadu and generate thousands of jobs in Rajasthan. In addition, I propose to add new mega clusters for Carpets in Srinagar (J&K) and Mirzapur (UP).

Health

58. The National Rural Health Mission is an essential instrument for achieving our goal of Health for all. I propose an increase of Rs. 2,057 crore over and above Rs.12,070 crore provided in the Interim Budget.

59. Rashtriya Swasthya Bima Yojana (RSBY) was operationalised last year. The initial response has been very good. More than 46 lakh BPL families in eighteen States and UTs have been issued biometric smart cards. This scheme empowers poor families by giving them freedom of choice for using health care services from an extensive list of hospitals including private hospitals. Government proposes to bring all BPL families under this scheme. An amount of Rs.350 crore, marking 40% increase over the previous allocation, is being provided in 2009-10 Budget Estimates.

Environment and Climate Change

60. The National Action Plan on Climate Change unveiled last year, outlines our strategy to adapt to Climate Change and enhance the ecological sustainability of our development path. Following this, eight national missions representing a multi-pronged, long-term and integrated approach are being launched. I propose to provide necessary funds for these missions.

61. Our government has already set up a 'National Ganga River Basin Authority' (NGRBA). I propose increasing the budgetary outlay for the National River and Lake Conservation Plans to Rs. 562 crore in 2009-10 from Rs. 335 crore in 2008-09.

62. I propose to make a special one-time grant of Rs.100 crore to the Indian Council of Forestry Research and Education, Dehradun in recognition of its excellence in the field of research, education and extension. I also propose an allocation of Rs.15 crore each for the Botanical Survey of India and Zoological Survey of India. An additional amount of Rs.15 crore is being allocated to Geological Survey of India.

TOWARDS BUILDING ACCOUNTABLE INSTITUTIONS

Improving delivery of public services

63. As substantial resources, both public and private, are mobilized to fuel the growth of the economy and make it more inclusive in character, efficiency of delivery must become the focus of government programmes. The enactment of the Right to Information Act at the Centre and in many states has been an important and successful step in this direction, ushering in greater transparency and accountability in the public decision-making process.

64. The setting up of the Unique Identification Authority of India (UIDAI) is a major step in improving governance with regard to delivery of public services. This project is very close to my heart. I am happy to note that this project also marks the beginning of an era where the top private sector talent in India steps forward to take the responsibility for implementing projects of vital national importance. The UIDAI will set up an online data base with

identity and biometric details of Indian residents and provide enrolment and verification services across the country. The first set of unique identity numbers will be rolled out in 12 to 18 months. I have proposed a provision of Rs.120 crore for this project.

National Security

65. For modernisation of Police force in the States, an additional amount of Rs.430 crore is being proposed, over and above the provisions in the Interim Budget. The Government has also sanctioned special risk/hardship allowances to the personnel of Para Military Forces at par with Defence forces. Provisions for payment of these allowances are also being proposed in the Budget.

66. For strengthening Border Management, an additional amount of Rs.2,284 crore, over and above the provision in the Interim Budget, is being provided for construction of fences, roads, flood-lights on the international borders.

67. Significant augmentation in the strength of para-military forces is being done. This calls for more investment in creating the necessary infrastructure, particularly in the area of housing. The Government, therefore, proposes to launch a massive programme of housing to create 1 lakh dwelling units for Central Para-Military Forces personnel. This will not only contribute to the morale of the forces, but will also enable leveraging of government's annual budgetary resources and create an innovative financing model.

One Rank One Pension for Ex-Servicemen (OROP)

68. Our country owes a deep debt of gratitude to our valiant Ex-Servicemen. The Committee headed by the Cabinet Secretary on OROP has submitted its report and the recommendations of the Committee have been accepted. On the basis of these recommendations the Government has decided to substantially improve the pension of pre 1-1-2006 defence pensioners below officer rank (PBOR) and bring pre 10-10-1997 pensioners on par with post 10-10-1997 pensioners. Both these decisions will be implemented from 1st July 2009 resulting in enhanced pension for more than 12 lakh jawans and JCOs. These measures will cost the exchequer more than Rs. 2,100 crore annually. Certain pension benefits being extended to war wounded and other disabled pensioners are also being liberalised.

Education

69. The demographic advantage India has in terms of a large percentage of young population needs to be converted into a dynamic economic advantage by providing them the right education and skills. The provision for the scheme, 'Mission in Education through ICT,' has been substantially increased to Rs. 900 crore. Similarly, the provision for setting up and up-gradation of Polytechnics under the Skill Development Mission has been increased to Rs. 495 crore. The government shall take forward its intent of having one Central University in each uncovered State and for this purpose I am allocating Rs. 827 crore. I

am also allocating Rs. 2,113 crore for IITs and NITs, which includes a provision of Rs. 450 crore for new IITs, and NITs. The overall Plan budget for higher education is proposed to be increased by Rs. 2,000 crore over Interim BE.

70. Union Territory of Chandigarh is the capital of Punjab and Haryana. The facilities at Panjab University, Chandigarh, need to be improved. I, therefore, propose to make an allocation of Rs.50 crore for this university. To enable the Union Territory Administration to provide better infrastructure to the people, I propose to suitably enhance the Plan allocation for Chandigarh during the current financial year.

Commonwealth Games 2010

71. The Commonwealth Games present the country with an opportunity to showcase our potential as an emerging Asian Power. I propose to substantially enhance the allocations for the Commonwealth Games from Rs. 2,112 crore in the Interim Budget to Rs. 3,472 crore in the Budget for 2009-10.

72. Madam Speaker, the Government is committed to ensure that Sri Lankan Tamils enjoy their rights and legitimate aspirations within the territorial sovereignty and framework of Sri Lanka's Constitution. The Ministry of External Affairs is working closely with the Sri Lankan Government in this regard. I propose to allocate Rs. 500 crore for the rehabilitation of the internally displaced persons, and reconstruction of the northern and eastern areas of Sri Lanka.

73. As Honourable Members are aware, Cyclone Aila struck the coast of West Bengal in the last week of May 2009. Extensive damage was caused to roads, houses and infrastructure. While immediate interim relief has been provided from the Calamity Relief Fund (CRF), it is proposed to draw up a programme for rebuilding the damaged infrastructure. For this purpose, I propose to allocate Rs.1,000 crore.

BUDGET ESTIMATES 2009-10

Madam Speaker, now I turn to the Budget Estimates for 2009-10.

74. The Budget Estimates 2009-10 provide for a total expenditure of Rs.10,20,838 crore consisting of Rs.6,95,689 crore towards Non Plan and Rs.3,25,149 crore towards Plan expenditure. The increase in Non Plan expenditure over BE 2008-09 is 37% whereas the increase in Plan expenditure is 34%. The total increase in expenditure in 2009-10 over BE 2008-09 is 36 per cent.

75. The increase in Non-Plan expenditure is mainly on account of the implementation of the Sixth Central Pay Commission recommendations, increased food subsidy and higher interest payment arising out of the larger fiscal deficit in 2008-09. Interest payments are estimated at Rs.2,25,511 crore constituting about 36% of Non-Plan revenue expenditure in BE 2009-10. The total provision for subsidies are up from Rs. 71,431 crore in BE 2008-09 to Rs.1,11,276 crore in BE 2009-10. The outlay on Defence has gone up from Rs. 1,05,600 crore in BE 2008-09 to Rs. 1,41,703 crore in BE 2009-10.

76. Honourable Members may recall that while presenting the Interim Budget 2009-10, I had stated that the Plan expenditure for 2009-10 may have to be increased further as a part of counter-cyclical measures to minimise the impact of global recession and economic slowdown. Against the backdrop of limited fiscal space because of reduction in CENVAT and Service Tax rates, Government have taken a conscious and bold decision to enhance the Gross Budgetary Support (GBS) for the Annual Plan 2009-10 by Rs. 40,000 crore over Interim Budget 2009-10. Bulk of this enhanced GBS is directed towards public investment in infrastructure with special emphasis on rural infrastructure, raising growth potential and leading to income generation. Besides, the State Governments will be permitted to borrow additional 0.5% of their GSDP by relaxing the fiscal deficit target under FRBM from 3.5% to 4% of their GSDP. This will enable the State Governments to raise additional open market loans of about Rs. 21,000 crore in the current year. In other words, the total additionality in Plan expenditure by Centre and the States put together would be Rs. 61,000 crore over Interim Budget. I do believe that this fiscal expansion will go a long way in reversing the impact of economic slowdown and accelerate our growth revival in the medium term.

77. Madam Speaker, given the possibility of the economic downturn persisting in the current year, the gross tax receipts are budgeted at Rs. 6,41,079 crore in BE 2009-10, compared to Rs. 6,87,715 crore in BE 2008-09. The non tax revenue receipts are, however, likely to be better and are estimated at Rs. 1,40,279 crore in BE 2009-10 compared to Rs. 95,785 crore in BE 2008-09. The revenue deficit as a percentage of GDP is projected at 4.8% compared to 1% in BE 2008-09 and 4.6% as per provisional accounts of 2008-09. The fiscal deficit as a percentage of GDP is projected at 6.8% compared to 2.5% in BE 2008-09 and 6.2% as per provisional accounts 2008-09. This level of deficit is a matter of concern and Government will address this issue in right earnest to come back to the path of fiscal consolidation at the earliest.

78. Madam Speaker, before I turn to my tax proposals, I cannot resist the temptation of re-visiting Kautilya. He said and I quote, "Just as one plucks fruits from a garden as they ripen, so shall a King have revenue collected as it becomes due. Just as one does not collect unripe fruits, he shall avoid taking wealth that is not due because that will make the people angry and spoil the very sources of revenue."

PART - B

TAX PROPOSALS

79. Madam Speaker, I shall now present my tax proposals.

80. As the House is aware, the thrust of reforms over the last few years, including the previous term of this Government, has been to improve the efficiency and equity of our tax system. This is sought to be achieved by eliminating distortions in the tax structure, introducing moderate levels of taxation and expanding the base. These

policy changes have been accompanied by requisite re-engineering of key business processes coupled with automation, both for direct and indirect taxes. On the direct tax side, a recent initiative for further improving efficiency is the setting up of a Centralized Processing Centre (CPC) at Bengaluru where all electronically filed returns, and paper returns filed in entire Karnataka, will be processed.

81. These tax reform initiatives have produced impressive results. The Centre's Tax-GDP ratio has increased to 11.5 per cent in 2008-09 from a low of 9.2 per cent in 2003-04. The healthy growth in tax revenues over the last five years is essentially attributable to growth in direct taxes. Further, the share of direct taxes in the Centre's tax revenues has increased to 56 per cent in 2008-09 from 41 per cent in 2003-04, reflecting a sharp improvement in the equity of our tax system. The Government is committed to furthering this process of tax reform.

82. In the course of preparation of this budget, I have had the opportunity to interact with large number of stakeholders and receive valuable inputs. Most suggestions were for structural changes in the tax system. Tax reform, like all reforms, is a process and not an event. Therefore, I propose to pursue structural changes in direct taxes by releasing the new Direct Taxes Code within the next 45 days and in indirect taxes by accelerating the process for the smooth introduction of the Goods and Services Tax (GST) with effect from 1st April, 2010.

83. The Direct Taxes Code, along with a Discussion Paper, will be released to the public for debate. Based on the inputs received, the Government will finalise the Direct Taxes Code Bill for introduction in this House sometime during the Winter Session.

84. To further enhance efficiency in tax administration, I intend to merge the two Authorities for Advance Rulings on Direct and Indirect Taxes by amending the relevant Acts. This will enable the Authority for Advance Rulings set up under Section 245-O of the Income Tax Act, 1961 to also function as the Authority for Advance Rulings for Indirect Taxes.

85. I have been informed that the Empowered Committee of State Finance Ministers has made considerable progress in preparing the roadmap and the design of the GST. Officials from the Central Government have also been associated in this exercise. I am glad to inform the House that, through their collaborative efforts, they have reached an agreement on the basic structure in keeping with the principles of fiscal federalism enshrined in the Constitution. I compliment the Empowered Committee of State Finance Ministers for their untiring efforts. The broad contour of the GST Model is that it will be a dual GST comprising of a Central GST and a State GST. The Centre and the States will each legislate, levy and administer the Central GST and State GST, respectively. I will reinforce the Central Government's catalytic role to facilitate the introduction of GST by 1st April, 2010 after due consultations with all stakeholders.

DIRECT TAXES

86. I shall now deal with direct taxes.

87. Madam Speaker, there have been demands by the corporate sector for reduction in tax rates. However, tax rates are determined by the size of the tax base; if the tax base is higher, the tax rates can be lower. The Income Tax Act is riddled with a plethora of tax exemptions which substantially erode the tax base. The extent of this erosion is presented to this House in the form of a Revenue Foregone Statement. The growth in the direct tax revenue foregone is relatively higher than the growth in the direct tax revenues. Accordingly, I do not propose to make any change in the Corporate Tax rates.

88. With a view to providing interim relief to small and marginal taxpayers and senior citizens, I propose to increase the personal income tax exemption limit by Rs. 15,000 from Rs. 2.25 lakh to Rs. 2.40 lakh for senior citizens. Similarly I also propose to raise the exemption limit by Rs. 10,000 from Rs. 1.80 lakh to Rs. 1.90 lakh for women tax payers and by Rs. 10,000 from Rs. 1.50 lakh to Rs. 1.60 lakh for all other categories of individual taxpayers. Further, I also propose to increase the deduction under section 80-DD in respect of maintenance, including medical treatment, of a dependent who is a person with severe disability to Rs. 1 lakh from the present limit of Rs. 75,000.

89. In the past, surcharges on direct taxes have generally been levied to meet the revenue needs arising from natural calamities. The Government has set up the National Calamity Contingency Fund to build up resources to meet emergency situations. As a corollary, surcharge on direct taxes should be removed. However, this has to be balanced with the revenue needs of the Government. Therefore, in the first instance, I propose to phase out the surcharge on various direct taxes by eliminating the surcharge of 10 per cent on personal income tax.

90. Deduction in respect of export profits is available under sections 10A and 10B of the Income-tax Act. The deduction under these sections would not be available beyond the financial year 2009-2010. In order to tide over the slowdown in exports, I propose to extend the sun-set clauses for these tax holidays by one more year i.e. for the financial year 2010-11.

91. The Finance Act, 2005 introduced the Fringe Benefit Tax on the value of certain fringe benefits provided by employers to their employees. This tax has been perceived as imposing considerable compliance burden. Empathising with these sentiments, I propose to abolish the Fringe Benefit Tax.

92. The competitive ability of an economy rests on its progress in the area of Research and Development (R&D). In order to incentivise the corporate sector to undertake R&D work, I propose to extend the scope of the current provision of weighted deduction of 150% on expenditure incurred on in-house R&D to all manufacturing businesses except for a small negative list.

93. Under the present scheme of the Income Tax Act, tax exemptions are largely profit-linked. Such incentives are inherently inefficient and liable to misuse. Therefore, it is proposed to incentivise businesses by providing investment-linked tax exemptions. To begin with, I propose to extend investment-linked tax incentives to the businesses of setting up and operating 'cold chain', warehousing facilities for storing agricultural produce and the business of laying and operating cross country natural gas or crude or petroleum oil pipeline network for distribution on common carrier principle. Under this method, all capital expenditure, other than expenditure on land, goodwill and financial instruments will be fully allowable as deduction.

94. Minimum Alternate Tax (MAT) was introduced to address inequity in taxation of corporate taxpayers. In the quest for greater equity, I propose to increase the rate of MAT to 15 per cent of book profits from the present rate of 10 per cent. However, to grant relief to corporate taxpayers, I also propose to extend the period allowed to carry forward the tax credit under MAT from seven years to ten years.

95. The New Pension System (NPS) is an important milestone in the development of a sustainable, efficient, voluntary and defined contribution pension system in India. While the NPS will continue to be subjected to the Exempt-Exempt-Taxed (EET) method of tax treatment of savings, it is proposed to provide necessary fiscal support to the NPS for the establishment of this much needed social security system. Accordingly, I propose to exempt the income of the NPS Trust from income tax and any dividend paid to this Trust from Dividend Distribution Tax. Similarly, all purchase and sale of equity shares and derivatives by the NPS Trust will also be exempt from the Securities Transaction Tax. I also propose to enable self employed persons to participate in the NPS and avail of the tax benefits available thereto.

96. In order to further improve the investment climate in the country, we need to facilitate the resolution of tax disputes faced by foreign companies within a reasonable time frame. This is particularly relevant for such companies in the Information Technology (IT) sector. I, therefore, propose to create an alternative dispute resolution mechanism within the Income Tax Department for the resolution of transfer pricing disputes. To reduce the impact of judgemental errors in determining transfer price in international transactions, it is proposed to empower the Central Board of Direct Taxes (CBDT) to formulate 'safe harbour' rules.

97. The Finance Act, 2008 introduced the Commodity Transaction Tax (CTT) to be levied on taxable commodities transactions entered in a recognized association. The Prime Minister's Economic Advisory Council has recommended abolition of the CTT. I, therefore, propose to abolish the Commodity Transaction Tax.

98. The House will agree that it is desirable to bring about transparency in the funding of political parties in the

country. With a view to reforming the system of funding of political parties, I propose to provide that donations to electoral trusts shall be allowed as a 100 per cent deduction in the computation of the income of the donor. For this purpose, Electoral Trusts will be such trusts as are set up as pass-through vehicles for routing the donations to political parties and are approved by CBDT.

99. Section 80E of the Income-tax Act provides for a deduction in respect of interest on loans taken for pursuing higher education in specified fields of study. I propose to extend the scope of this provision to cover all fields of study, including vocational studies, pursued after completion of schooling.

100. Anonymous donations to charitable institutions are presently liable to tax so as to prevent unaccounted money being routed to such entities in the garb of anonymous donations. However, some organisations are facing genuine problems in complying with the procedural requirements. In order to mitigate the practical difficulties being faced by such charitable organisations, I propose to grant relief to such organisations by not taxing anonymous donations received to the extent of 5 per cent of their total income or a sum of Rs. 1 lakh, whichever is higher.

101. To facilitate the business operations of all small taxpayers and reduce their compliance burden, I propose to expand the scope of presumptive taxation to all small businesses with a turnover up to Rs. 40 lakhs. All such taxpayers will have the option to declare their income from business at the rate of 8 per cent of their turnover and simultaneously enjoy exemption from the compliance burden of maintaining books of accounts. As a procedural simplification, I also propose to allow them to pay their entire tax liability from business at the time of filing their return by exempting them from paying advance tax. This new scheme will come into effect from the financial year 2010-11.

102. Madam Speaker, in the context of the geopolitical environment, it is necessary for us to create our own facilities for energy security. Accordingly, I propose to extend the tax holiday under section 80-IB(9) of the Income Tax Act, which was hitherto available in respect of profits arising from the commercial production or refining of mineral oil, also to natural gas. This tax benefit will be available to undertakings in respect of profits derived from the commercial production of mineral oil and natural gas from oil and gas blocks which are awarded under the New Exploration Licensing Policy-VIII round of bidding. Further, I also propose to retrospectively amend the provisions of the said section to provide that "undertaking" for the purposes of section 80-IB(9) will mean all blocks awarded in any single contract.

103. Under the present provisions of section 2(15) of the Income Tax Act, "charitable purpose" includes relief of the poor, education, medical relief, and the "advancement of any other object of general public utility". However, the "advancement of any other object of general public utility" cannot involve the carrying on of any activity in the nature

of trade, commerce or business. I propose to provide the same tax treatment to trusts engaged in preserving and improving our environment (including watersheds, forests and wildlife) and preserving our monuments or places or objects of artistic or historic interest, as is available to trusts engaged in providing relief of the poor, education and medical relief.

INDIRECT TAXES

104. Madam Speaker, I turn to my main proposals on indirect taxes.

105. I will first take up customs duties.

106. Although our domestic industry has weathered the impact of the global financial crisis and the resultant slowdown with resilience, it is yet to fully find its feet. Manufacturing growth, which had turned negative in October, 2008 on a year-on-year basis and remained in that zone till March this year, appears to be barely turning the corner. However, the global scenario remains worrisome and it is my view that the paramount need is to provide industry with a stable framework. My proposals on indirect taxes seek to achieve this by maintaining the overall rate structure for customs and central excise duties as well as service tax. I must hasten to add that I have not hesitated to act where distortions provide a compelling reason or where relief would provide a healing touch.

107. Full exemption from basic customs duty was provided to Set Top Boxes in 2006 to enable their free import for the smooth introduction of the Conditional Access System (CAS). Now that production capacity has come up in the country, I propose to impose a nominal basic customs duty of 5 per cent on such Set Top Boxes to encourage domestic value addition.

108. The electronic hardware industry has a strong potential for creating employment especially in the SME sector. I intend to reduce the basic customs duty on LCD panels from 10 per cent to 5 per cent to support indigenous production of LCD televisions.

109. Full exemption from CVD of 4 per cent was available to accessories, parts and components imported for the manufacture of mobile phones till the 30th of June, 2009. I propose to reintroduce this exemption for another year.

110. For reasons that are apparent, industry sectors having an export-orientation have been adversely impacted by the demand compression in global markets. Presently, exporters of leather products, textile garments, footwear as well as sports goods are permitted to import raw materials, consumables etc. up to 3 per cent of the fob value of their exports free of duty. I propose to add a few more items to these lists. Full exemption from basic customs duty is being provided to rough corals for encouraging value-addition and export.

111. It is imperative that the contribution of new and renewable energy sources of power is enhanced if we have to successfully combat the phenomena of global warming and climate change. I am reducing the basic

customs duty on permanent magnets - a critical component for Wind Operated Electricity Generators - from 7.5 per cent to 5 per cent.

112. On influenza vaccine and nine specified life saving drugs used for the treatment of breast cancer, hepatitis-B, rheumatic arthritis etc. and on bulk drugs used for the manufacture of such drugs, I propose to reduce the customs duty from 10 per cent to 5 per cent. They will also be totally exempt from excise duty and countervailing duty.

113. Customs duty will also be reduced from 7.5 per cent to 5 per cent on two specified life saving devices used in treatment of heart conditions. These devices will be fully exempt from excise duty and CVD also.

114. Gold bars currently attract customs duty at the specific rate of Rs.1 00 per ten grams while other forms of gold (excluding jewellery) are chargeable to a duty of Rs.250 per ten grams. These rates were fixed in 2004 and have not been reviewed even as the price of gold has increased manifold. I propose to partially restore the incidence by increasing these rates to Rs.200 per ten grams and Rs.500 per ten grams respectively. Along the same lines, the customs duty on silver (excluding jewellery) will be increased from Rs.500 per kg to Rs.1,000 per kg. These revised rates would also apply to gold and silver, including ornaments that are not studded, when imported by a bona fide passenger as baggage.

115. I will now come to central excise duties.

116. Hon'ble Members are aware that the Government announced a series of fiscal stimulus packages, one of the key elements of which was the sharp reduction in the ad valorem rates of Central Excise duty for non-petroleum products by 4 percentage points across the board on 7th of December, 2008 and by another 2 percentage points in the mean CENVAT rate on the 24th of February, 2009.

117. One of the consequences of these cuts was that pure cotton textiles came to be fully exempted from excise duty. We have received representations that full exemption prevents manufacturers from availing of export rebate of the duty paid from CENVAT credit. I propose to rectify this situation by restoring the erstwhile optional rate of 4 per cent for cotton textiles beyond the fibre stage.

118. Ever since the revamp of the excise duty structure on textiles by my distinguished predecessor in the 2004 budget, a differential in rates has been maintained between the cotton sector and the manmade sector. In keeping with the integrity of the earlier structure, I propose to restore the rate of 8 per cent Central Excise duty on manmade fibre and yarn on a mandatory basis and on stages beyond fibre and yarn at that rate on optional basis. These changes, together with duty changes on intermediates, would imply that the duty on all types of manmade fibre and yarn and their intermediates would be the same, easing the problem of credit accumulation.

119. Wool waste and cotton waste are chargeable to basic customs duty of 15 per cent. These are used in the

manufacture of cheaper varieties of textile articles such as blankets and rugs. As a measure of relief to this sector, I propose to reduce the basic customs duty on these items to 10 per cent.

120. With the Government's proclaimed objective of introducing a Goods and Services Tax (GST) both at the national and State level, some more steps in that direction are necessary. One measure that would facilitate the process is the further convergence of central excise duty rates to a mean rate - currently 8 per cent. I have reviewed the list of items currently attracting the rate of 4 per cent, the only rate below the mean rate. There is a case for enhancing the rate on many items appearing in this list to 8 per cent, which I propose to do, with the following major exceptions :

- * food items; and
- * drugs, pharmaceuticals and medical equipment.

Some of the other items on which I propose to retain the rate of 4 per cent are:

- * paper, paperboard and their articles;
- * items of mass consumption such as pressure cookers, cheaper electric bulbs, low-priced footwear, water filters/purifiers, CFL etc.;
- * power-driven pumps for handling water; and
- * paraxylene.

The details are available in the relevant notifications.

121. Bio-diesel, obtained from vegetable oils and used for blending with petrodiesel, is currently exempt from excise duty. I now propose to fully exempt petro-diesel blended with bio-diesel from excise duty.

122. In order to encourage the use of this environment friendly fuel and augment its availability in the country, I also propose to reduce basic customs duty on bio-diesel from 7.5 per cent to 2.5 per cent - at par with petro-diesel. With these proposals I hope to see a smile on the faces of the green brigade!

123. My other proposals on central excise duties seek to address distortions that the manufacturing industry has been complaining about.

124. The IT industry has pointed out that it is facing difficulties in the assessment of software which involves transfer of the right to use after the levy of service tax on IT software service. To resolve the matter, I propose to exempt the value attributable to the transfer of the right to use packaged software from excise duty and CVD.

125. The construction industry has represented that they are facing difficulties on account of withdrawal of exemption on goods manufactured at site. I propose to restore full exemption to such goods, including pre-fabricated concrete slabs or blocks, when used for further construction at site.

126. A specific component was added to the ad valorem duty of 24 per cent applicable to large cars and utility vehicles in June last year. In the case of vehicles of

engine capacity below 2000 cc, this component was Rs.15,000 per unit while for vehicles of higher engine capacity it was Rs. 20,000 per unit. These rates are now being unified at the lower level of Rs. 15,000 per unit.

127. Petrol driven trucks provide a useful means of transport within cities and across short distances. These are chargeable to excise duty of 20 per cent. I propose to reduce excise duty on these trucks to 8 per cent to equate the duty with similar vehicles run on diesel.

128. Madam Speaker, I fear that my proposals relating to gold and silver on the customs side would somewhat dent my popularity with women. I propose to salvage this by fully exempting branded jewellery from excise duty.

129. I now turn to my proposals on service tax.

130. It is an international practice to zero-rate exports. To achieve this objective, a scheme was announced in 2007, granting refund of service tax paid on certain taxable services used after the clearance of export goods from the factory. For some time now, the exporting community has been expressing dissatisfaction over the difficulties faced in obtaining such refunds. Several procedural simplifications attempted in the past have also not yielded satisfactory results. The solution seems to lie in placing greater trust on the claims filed by the exporters. Keeping this in view, I propose to make the following changes in the scheme:

- * Services received by exporters from goods transport agents and commission agents, where the liability to pay service tax is *ab initio* on the exporter, would be exempted from service tax. Thus, there would be no need for the exporter to first pay the tax and later claim refund.
- * For other services received by exporters, the exemption would be operated through the existing refund mechanism based on self certification of the documents where such refund is below 0.25 per cent of fob value, and certification of documents by a Chartered Accountant for value of refund exceeding the above limit.

131. The Export Promotion Councils and the Federation of Indian Export Organizations (FIEO) provide a valuable service in augmenting our export effort. I propose to exempt them from the levy of service tax on the membership and other fees collected by them till 31st March, 2010.

132. In the goods transport sector, service tax is currently levied on transport of goods by road, by air, through pipelines and in containers. However, goods carried by Indian railways or those carried as coastal cargo or through inland waterways are not charged to service tax. In order to provide a level playing field in the goods transport sector, I propose to extend the levy of service tax to these modes of goods transport. The new levy is not likely to impact the prices of essential commodities or goods

for mass consumption, as suitable exemptions would be provided.

133. As the Hon'ble Members are aware, services provided by chartered accountants, cost accountants, and company secretaries as well as by engineering and management consultants are presently charged to service tax. Although there is a school of thought that legal consultants do not provide any service to their client, I hold my distinguished predecessor in high esteem and disagree! As such, I propose to extend service tax on advice, consultancy or technical assistance provided in the field of law. This tax would not be applicable in case the service provider or the service receiver is an individual.

134. Vehicles having 'Stage Carriage Permits' and run by State undertakings are exempted from service tax. However, transportation of passengers undertaken by private enterprises in vehicles having 'Contract Carriage Permits' is, subjected to service tax. In order to bring parity in tax treatment, I propose to exempt such transportation also from the levy of service tax.

135. In July, 2008 goods transport agents (GTA) went on strike with several demands. One of the demands that was accepted by the government was to exempt certain services, such as packing, cargo handling and warehousing, provided to GTAs en route, from service tax. For this purpose an exemption notification was issued. It was also demanded by goods transport agents that the proceedings already initiated against such service providers should be dropped.

The Government has accepted this genuine demand. Therefore, I propose to make certain legislative changes required to fulfil this promise.

136. Copies of notifications giving effect to the changes in customs, central excise and service tax will be laid on the Table of the House in due course.

137. My tax proposals on direct taxes are revenue neutral. On indirect taxes, they are estimated to yield a net gain of Rs. 2,000 crore for a full year.

CONCLUSION

138. As we begin this five-year journey, the road ahead will not be easy. We will have to manage uncertainties and there will be as many problems as there would be solutions. Mahatma Gandhi said and I quote, "Democracy is the art and science of mobilizing the entire physical, economic and spiritual resources of various sections of the people in the service of the common good of all." This is precisely what we will have to do. With strong hearts, enlightened minds and willing hands, we will have to overcome all odds and remove all obstacles to create a brave new India of our dreams.

139. Madam Speaker, with these words I commend the budget to the House."

SHAKTIKANTA DAS, Jt. Secy. (Budget)